● वर्ष-3
● अंक-297
रायपुर, गुरुवार
25 जुलाई 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› ये हैं सफलता के मंत्र

कानून व्यवस्था पर स्थगन अग्राह्य, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का कांग्रेस पर तंज

साय सरकार बदले की राजनीति नहीं करती

रायपुर. छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन आज कानून व्यवस्था पर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाया और चर्चा की मांग की. आसंदी ने स्थगन को ग्राह्य नहीं किया, लेकिन ग्राह्यता पर चर्चा की अनुमति दी. स्थगन प्रस्ताव के ग्राह्यता पर दो घंटे से ज्यादा समय तक चर्चा हुई. इस दौरान पक्ष-विपक्ष में जमकर तकरार देखने को मिली. विपक्ष के सदस्यों ने सत्ता पक्ष पर जमकर आरोप लगाया. पक्ष के सदस्यों ने भी इसका कड़ा प्रतिकार किया.

गृहमंत्री विजय शर्मा ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा, विपक्ष के सदस्य ये न बताए कि एफआईआर कैसे दर्ज होती है, धाराएं कैसे लगाई जाती है. मैं इस बात से भली भांति परिचित हूं. मुझ पर एफआईआर दर्ज की गई थी. मेरे ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगाया गया था. मुझे जेल भेजा गया था. ये बताने का मतलब ये नहीं जैसा पूर्व की सरकार में हुआ वैसा ही अब होगा. हमारी सरकार किसी पर बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करती. हम प्रदेश में सुशासन लाना चाहते हैं.

गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बिरनपुर में कैसे हत्या हुई थी? अनुसूचित जनजाति के युवाओं ने कैसे नग्न प्रदर्शन किया था? सुकमा एसपी ने धर्मांतरण को लेकर क्या पत्र लिखा था? मंदिर हसौद में राखी के दिन नाबालिग बहनों के साथ क्या हुआ था? जयस्तंभ चौक पर किस तरह से हमला हुआ था? रायपुर में एडिशनल एसपी के कार्यालय के नीचे कैसे एक युवती के साथ दुष्कर्म हुआ था? बलात्कार की घटना पर कैसे तब की सरकार के मंत्री ने कहा था कि उत्तर प्रदेश का बलात्कार बड़ा और छत्तीसगढ़ का छोटा होता है? भिलाई में किस तरीके से 32 वर्षीय मलकीत सिंह ने हिंदुस्तान कहा था तो उसे मार डाला गया था? खुरमुडा में सामूहिक नरसंहार हुआ था?

गृहमंत्री ने आगे कहा, कवर्धा में अपराध सुनते सुनते मेरे कान पक गये हैं. कवर्धा में जाने कैसा प्रशासन चल रहा था. फर्जी एफ़आइआर दर्ज की जाती थी. एक बैगा आदिवासी ने थाने में आत्महत्या कर ली थी. एक उंगली दिखाएंगे तो तीन उंगलियां उस तरफ होंगी. हमारी सरकार के छह महीने में अपराध की घटना कम हुई है. कोयला घोटाला पर भी जांच पुख़्ता ढंग से चालू है. 25 रुपए टन की वसूली पर रोक लगाने पारदर्शिता लाई गई है. पिछली सरकार ने ऑफ लाइन प्रक्रिया शुरू कर दी थी. इसे साय सरकार ने हटा दिया है. आज पारदर्शिता के साथ कोयला ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है. बलौदबाजार की घटना का दुख है. इस पर भी जांच के बाद स्थिति साफ होगी.

पूर्व मंत्री और विधायक राजेश मूणत ने

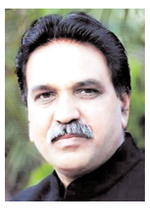

कहा, पूर्व मंत्री को 48 घंटे धरना देना पड़ा था. बाथरूम जाने तक की व्यवस्था नहीं थी. किस नैतिकता की बात विपक्ष कर रहा है. नकली सीडी के अभियुक्त भी यहां बैठे हैं. पिछली सरकार ने सीबीआई पर प्रतिबंध लगा दिया था. अब साय सरकार ने प्रतिबंध हटा दिया है. अब सीबीआई जांच तेज होगी. अजय चंद्राकर ने कहा कि भिलाई में भी एक सीडी आई है. उस सीडी में एक विधायक की तरह शख़्स दिख रहा है. इसकी भी सीबीआई जांच कर लेनी चाहिए. विधायक ने ख़ुद सीबीआई जांच की मांग की है. गृहमंत्री को सीबीआई जांच की घोषणा करनी चाहिए.

सत्ता के संरक्षण में हो रही घटनाएं : भूपेश बघेल

इससे पहले स्थगन प्रस्ताव पेश करते हुए

कांग्रेस विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, रायपुर में ही चार बार गोलियां चल चुकी है. गैंगस्टर प्रदेश में आ रहे हैं. गैंगस्टर के शूटर फ़ायरिंग कर रहे हैं. लूट डकैती, चाकूबाज़ी की घटनाएं बढ़ गई है. रायगढ़ में देसी कट्टे के दम पर लूटपाट हो रही है. व्यापारियों-उद्योगपतियों को धमकाया जा रहा है. गाय की मुंडी काटकर लटकाया जा रहा है. मॉब लिंचिंग हो रही है. सत्ता के संरक्षण में घटना हो रही है. सिर्फ पता पूछने पर एक आदिवासी लड़के की राजधानी में हत्या कर दी गई. भूपेश बघेल ने कहा, मारवाही में दिनदहाड़े एक युवती की हत्या कर दी गई. पूरा पुलिस महकमा किसी और काम में लग गया है. पहले ट्रांसफ़र होता है फिर उसे रुकवाया जाता है. पूरे प्रदेश में साइबर क्राइम में बढ़ोतरी हो रही है. आपराधिक मामलों में छत्तीसगढ़ की रैंकिंग बढ़ती जा रही है. अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है. मादक पदार्थों का मुख्य अड्डा छत्तीसगढ़ बन गया है. राज्य के तस्करों का सीधा संबंध ओड़िशा के गांजा तस्करों से हो गया है.

कांग्रेस सरकार के 6 माह में नहीं हुई इतनी घटनाएं : चरणदास महंत

नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा, साय

सरकार में 6 महीने में 562 हत्या हुई है. चोरी, दुष्कर्म, ठगी, तस्करी सभी अपराधों को जोड़कर 6 महीने के भीतर 12458 घटनाएं हुई है. इसमें केवल 8307 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं. क्या एक दुष्कर्म के लिए एक दोषी नहीं मिला. अब इसको पुलिस का संरक्षण मिल रहा है तो आप लोगों को तकलीफ हो रही है. इन बातों को सुनकर आप ग्राहयता के लिए तैयार नहीं होंगे तो हम कब अपनी बात रखेंगे. आप अब हमारी बात सुनकर इसे स्वीकार कर लिए, बाकी बात हम विस्तार से रखेंगे. नेता प्रतिपक्ष ने कहा, भूपेश बघेल की सरकार में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 6 महीने में इतनी घटनाएं सामने आई हो.

अपराध में दूसरे राज्यों से आगे निकल गया छत्तीसगढ़ : लखमा

स्थगन ग्राहता पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक कवासी लखमा ने कहा, 7 महीने में ही विष्णुदेव साय सरकार फेल हो गई है. 7 महीने में कानून व्यवस्था इतनी खराब हो गई कि छत्तीसगढ़ अपराध के मामले में बिहार और यूपी जैसे राज्य से आगे निकल गया है. दूसरे राज्य के अपराधी गोलीकांड करके फरार हो जाते हैं. भाजपा की सरकार जब आती है, किसान, आदिवासी जेल भेजे जाते हैं. राजधानी में पैदल चलने वाली महिलाएं सुरक्षित नहीं है. आदिवासी छात्र की हत्या राजधानी में हो जाती है. भाजपा सरकार में सलवा जुडूम के नाम पर लाखों आदिवासी विस्थापित हो गए. हमारे नवजवान गृहमंत्री से कहना चाहेंगे

कि बस्तर में शांति हो, लेकिन बस्तर में ऐसा हो नहीं रहा है.

पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने कहा, रायगढ़ में हरि नाम के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई. रायगढ़ में एक पत्रकार को पीटा गया. उसका बयान तक पुलिस दर्ज नहीं करती. एसपी को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग करने पर भी पुलिस की हिम्मत नहीं होती कि एफ़आईआर दर्ज कर लिया जाए. पुलिस की धमक होनी चाहिए. पुलिस का इकबाल होना चाहिए.

कांग्रेस विधायक रामकुमार यादव ने कहा कि दो-चार नाम वो भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नाम लेकर गिनाने से पूर्व में और अभी अपराध कम हो गया ये कहना गलत है. संख्या तो हजारों अपराधों की है. कांग्रेस विधायक द्वारिकाधीश यादव ने कहा कि घटना जो घटी उसमें एफआईआर धारा कम जोड़ी जा रही है, कहीं-कहीं छोटी घटनाओं में धाराएं बढ़ा दी जा रही है.

आरएसएस और अंग्रेज जमाने की बात पर जमकर हुई बहस

स्थगन ग्राहता पर चर्चा के दौरान आरएसएस और अंग्रेज जमाने की बात होने लगी. गृहमंत्री ने कहा, कांग्रेस का कार्यालय अंग्रेजों का कार्यालय रहा है. मंत्री के इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कड़ी आपत्ति की. बघेल ने कहा कि ऐसा कहना अनुचित है और अपमानजनक है. इस दौरान उमेश पटेल ने कहा कि आरएसएस के कार्यालय में आज तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया. उमेश पटेल की इस टिप्पणी के बाद पक्ष और विपक्ष के बीज जमकर बहस और नारेबाजी हुई. भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि एक भी कांग्रेस का सदस्य आजादी की लड़ाई में शहीद नहीं हुआ. इस बयान पर कांग्रेस विधायकों ने जमकर नारेबाजी की. कांग्रेस ने माफी मांगने की मांग की.

बजट भाषण में दिखा वित्तीय इंजीनियरिंग की कुशलता

शंकर अय्यर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 7,800 शब्दों वाले करीब नब्बे मिनट के बजट भाषण में वित्तीय इंजीनियरिंग की कुशलता व राजनीति का सटीक प्रबंधन दिखता है। बजट दरअसल पवित्र राजनीतिक मंशा की एक अभिव्यक्ति होता है। सरकार के लिए यह राजनीतिक सहयोगियों को आश्वस्त करने का एक अवसर है, लेकिन साथ ही यह आर्थिक आवेगों को भी बढ़ावा देता है। 2024 का बजट राजनीतिक मजबूरियों और आर्थिक अनिवार्यताओं के चौराहे पर पहुंचा है। लोकसभा चुनावों के दौरान बयानबाजी का सिलसिला, सत्ताधारियों के संख्याबल में कमी और जीडीपी में वृद्धि व निजी उपभोग के दावों और 'फील-गुड' कारक के बीच की दूरी ने राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उम्मीदें बढ़ा दी थीं।

बजटों का शिल्प, कला और विज्ञान दोनों होता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 7,800 शब्दों वाले करीब नब्बे मिनट के भाषण में आय पिरामिड में सबसे नीचे से आने वाली दर्द भरी चीखों का सुनना दिखता है। बजट में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ किए जाने की कोशिश है।

बजट राजनीति का कुशल प्रबंधन वित्तीय इंजीनियरिंग में दिखाई देता है। बजट से पहले दो सहयोगियों तेदेपा और जदयू ने अपने समर्थन की कीमत जाहिर कर दी थी, जिसे पूरा भी किया गया है। नए बजट में वे सभी बातें हैं, जो लोग सरकार से सुनना चाहते हैं। बजट में नौ प्राथमिकताएं सूचीबद्ध हैं। बजट लोकलुभावन वादों को छोड़ संरचनात्मक दृष्टिकोण का विकल्प चुनता है। इसमें कृषि अनुसंधान, उच्च उपज वाले बीज जारी करने, प्राकृतिक खेती की शुरुआत, दालों और तिलहनों के लिए मिशन, खराब होने वाली वस्तुओं के लिए क्लस्टर, डिजिटल सर्वेक्षण, किसान क्रेडिट कार्ड के विस्तार, मवेशियों और झींगा पालन के लिए वित्तपोषण की समीक्षा की पेशकश की गई। सरकार ने बेरोजगार युवाओं की बात सुनी और रोजगार से जुड़ा एक प्रोत्साहन कार्यक्रम तैयार किया है, जिसमें नियोक्ताओं को लागत में छूट, शिक्षार्थियों को वित्तीय मदद, और नौकरी चाहने वालों को मौके शामिल हैं।

बजट टीम भारत के विचार को पुनर्जीवित करने के लिए एक रूपरेखा का वादा करती है, जिसमें राज्यों व केंद्र में समरूपता होगी। बजट में शहरीकरण की शक्ति को भी पहचाना गया है। इन्हें विकास का केंद्र माना गया है, लेकिन इतना काफी नहीं, क्योंकि भारत में शहरों के प्रबंधन को बदलने के लिए प्रतिमानों में बड़ा बदलाव जरूरी है। इसमें संदेह नहीं कि बजट में कई आशाजनक बिंदु हैं। सब कुछ कहने और हो जाने के बाद यह देखना बाकी है कि जो कहा गया है, वह पूरा होता है या नहीं। यह वास्तव में उम्मीद की लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा है।

नेपाल में काठमांडू एयरपोर्ट पर विमान हादसा हो गया. इसमें 19 लोग सवार थे, जिसमें से 18 लोगों की मौत हो गई जबकि एक पायलट का इलाज अस्पताल में चल रहा है.

प्रमुख समाचार

रेवंत रेड्डी भी करेंगे नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार

नई दिल्ली। बजट को लेकर केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गया है। यही कारण है कि विपक्ष शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और उनके कर्नाटक समकक्ष सिद्धारमैया के एक दिन बाद, तेलंगाना के सीएम ए रेवंत रेड्डी ने भी नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है। रेड्डी ने कहा कि बहिष्कार को विरोध के रूप में चिह्नित किया जाएगा। केंद्र ने कथित तौर पर तेलंगाना के अधिकारों को चोट पहुंचाई और इसके लिए धन जारी नहीं किया। उन्होंने विधानसभा में सरकार के फैसले की घोषणा की। विधानसभा ने दिन भर की बहस के बाद केंद्रीय बजट में राज्य के प्रति केंद्र के कथित भेदभाव के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया। हालांकि, विपक्षी बीजेपी ने सदन में इस प्रस्ताव का विरोध किया। कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। उनका दावा है कि केंद्रीय बजट में राज्य की मांगों की उपेक्षा करने के विरोध में कर्नाटक इस बैठक का बहिष्कार करेगा।

शरद के साथ जाने का मन बना चुके हैं क्या अजित

मुंबई। विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत तेज होने के बीच महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान राकांपा के लिए 80-90 सीटों की मांग की है। अमित शाह के साथ अपनी बैठक के दौरान अजीत पवार ने सीट वितरण को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने और लोकसभा चुनाव की तरह आखिरी मिनट तक इधर-उधर भटकने से बचने पर जोर दिया। सूत्रों ने कहा कि अजित पवार उन 54 सीटों पर चुनाव लड़ने पर अड़े थे जो संयुक्त राकांपा ने 2019 के विधानसभा चुनावों में जीती थीं। इनके अलावा अजित पवार की नजर पश्चिमी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तरी महाराष्ट्र (खानदेश) क्षेत्र से कांग्रेस के खिलाफ 20 सीटों पर लड़ने पर है। उपमुख्यमंत्री मुंबई में कांग्रेस के खिलाफ अल्पसंख्यक समुदाय के प्रभुत्व वाली 4-5 सीटों पर चुनाव लड़ने के भी इच्छुक हैं। सूत्रों ने कहा कि अजित पवार को अपनी पार्टी से तीन निर्दलीय और तीन कांग्रेस विधायकों के चुनाव लड़ने का भी भरोसा है।

महाराष्ट्र में कर दिया चुनाव में भाजपा के साथ बड़ा खेल

मुंबई। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चन्द्रशेखर बावनकुले ने कहा कि हम सभी ने चुनाव आयुक्त से मुलाकात की और 11 विषयों पर चर्चा की है। हमने लोकसभा में देखा है, अगर हम नागपुर की बात करें तो 1 लाख से अधिक वोट हटा दिए गए। जिन्होंने 2019 में मतदान किया। 36,000 नाम पूरी तरह से हटा दिए गए। जिन नए मतदाताओं ने अपना नाम दर्ज कराया, उनका उल्लेख सूची में नहीं है। हमने इसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चोकलिंगम को देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, इसलिए हम मुख्य चुनाव आयोग को बताने आए। चुनावी धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए, महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चन्द्रशेखर बावनकुले ने राज्य की चुनावी प्रक्रियाओं में एक बड़ी साजिश का दावा किया है। विधानसभा चुनाव से पहले वोट हेरफेर में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह किया है। महाराष्ट्र में भाजपा अध्यक्ष चन्द्रशेखर बावनकुले ने कहा कि दो विधानसभा क्षेत्रों के लिए कम से कम 3000 मतदाता पंजीकृत थे, जो उनके अनुसार, एक विशेष समुदाय के थे। धुले और मालेगांव विधानसभा क्षेत्र में 3000 से अधिक प्रविष्टियां हैं जो धुले के साथ-साथ मालेगांव में भी हैं।

शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिष्ठित लोगों की एक समिति बनाने का प्रस्ताव दिया है। ये समिति किसानों और अन्य हितधारकों से मिलकर उनकी बात सुनेगी और ऐसा व्यवहारिक समाधान खोजेगी, जो निष्पक्ष, न्यायसंगत और सभी के हित में हो। सुप्रीम कोर्ट ने अंबाला के पास शंभू सीमा पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। शंभू सीमा पर किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह एक स्वतंत्र समिति गठित करने का प्रस्ताव देता है। यह समिति किसानों और अन्य हितधारकों से संपर्क उनकी मांगों का व्यावहारिक समाधान निकालेगी, जो निष्पक्ष, न्यायसंगत और सभी के हित में हो। गौरतलब है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे-1 पर शंभू बॉर्डर को एक सप्ताह में खोलने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, 24 जुलाई यानी आज तक शंभू बॉर्डर को खोला जाना था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। हरियाणा सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। हरियाणा हाईकोर्ट पर सुनवाई करते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और कहा कि शंभू बॉर्डर के पास यथास्थिति बनाए रखी जाए, जहां किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं।

उमर की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब

नई दिल्ली। सितंबर 2020 में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए खालिद ने मामले में जमानत देने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के हालिया आदेश पर सवाल उठाया है।दिल्ली हाईकोर्ट ने फरवरी 2020 में नई दिल्ली में हुए दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा है। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस गिरीश कठपालिया की पीठ सुनवाई 29 अगस्त तय की है। पीठ ने साथ ही मामले में छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम सहित अन्य सह-आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर भी सुनवाई की। अदालत ने पाया कि इमाम और मामले में अन्य सह-आरोपियों की जमानत याचिकाएं सुनवाई के लिए निर्धारित हैं। सितंबर 2020 में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए खालिद ने मामले में जमानत देने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के हालिया आदेश पर सवाल उठाया है। खालिद, इमाम और कई अन्य लोगों पर फरवरी 2020 के दंगों के कथित मास्टरमाइंड होने के लिए आतंकवाद विरोधी कानून, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज

विपक्ष का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल,

भाजपा ने कहा- बजट में सभी का रखा गया ध्यान

संसद ने आज केंद्रीय बजट 2024 और 2024-2025 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के बजट पर चर्चा शुरू की। बुधवार को कार्यवाही हंगामेदार ढंग से शुरू हुई। विपक्षी सांसदों ने बजट के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया। इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने आरोप लगाया है कि बजट गैर-भाजपा शासित राज्यों के साथ भेदभावपूर्ण है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट पेश किया था। अपने सातवें रिकॉर्ड बजट में, निर्मला सीतारमण ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और पर्याप्त अवसर पैदा करने के उद्देश्य से प्रमुख प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। इनमें कृषि, रोजगार और कौशल और सेवाओं में उत्पादकता और लचीलापन शामिल था।

लोकसभा की बैठक बुधवार को हंगामे के साथ शुरू हुई और विपक्षी सदस्यों ने राज्यों के बजटीय आवंटन का मुद्दा सदन में उठाने का प्रयास किया लेकिन आसन से अनुमति नहीं मिलने पर उन्होंने सदन से वाकआउट किया जिसके बाद सदन में कामकाज सुचारू तरीके से हुआ।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने केंद्रीय बजट में कई राज्यों के साथ ''भेदभाव' से जुड़े विपक्ष के आरोप को खारिज करते हुए बुधवार को लोकसभा में कहा कि इसमें सभी प्रदेशों और वर्गों का ध्यान रखा गया है तथा जनता के लिए आज भी 'मोदी की गारंटी' कायम है। वर्ष 2024-25 के लिए बजट पर लोकसभा में सामान्य चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद विप्लव कुमार देव ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत में पारदर्शी आर्थिक व्यवस्था लागू की गई है।

कांग्रेस ने केंद्रीय बजट को 'कुर्सी बचाओ और जुमला बजट' करार देते हुए बुधवार को कहा कि इस बजट में सिर्फ दो राज्यों बिहार और आंध्र प्रदेश पर मेहबरानी की गई है, लेकिन देश के अन्य राज्यों, किसानों और गरीबों की अनदेखी की गई है। वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पर लोकसभा में सामान्य चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने यह दावा भी किया कि 'कुर्सी को बचाओ और मित्रों पर लुटाओ' इस सरकार का आखिरी नारा है।

गुजरात में चांदीपुरा वायरस से अब तक 37 बच्चों की मौत होने का दावा करते हुए कांग्रेस की सांसद गनीबेन नगाजी ठाकोर ने केंद्र सरकार से इस

विषाणु के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जल्द से जल्द सख्त कदम उठाने की मांग की और कहा कि इसे गंभीरता से नहीं लिया गया तो दोबारा कोरोना महामारी जैसी भयानक स्थिति पैदा हो सकती है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि महाराष्ट्र में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र में वडसा-गढ़चिरौली रेलवे लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण और वन मंजूरियों के बाद काम ने रफ्तार पकड़ ली है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान गढ़चिरौली-चिमूर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के सदस्य किरसन नामदेव के पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए वैष्णव ने कहा कि परियोजना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों से होकर गुजरती है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि केरल सरकार रेलवे परियोजनाओं के संदर्भ में बहुत सहयोगी नहीं रही है और यदि राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण में सहयोग करे तो बहुत काम किया जा सकता है। वैष्णव ने केरल में प्रस्तावित आंगामाली-सबरीमला रेल मार्ग परियोजना से संबंधित पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए यह बात कही।

सरकार की तेलंगाना में सिंगरेनी कोयला खदान कंपनी के निजीकरण की कोई योजना नहीं है तथा इसे और मजबूत करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। कोयला एवं खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने बुधवार को यह बात लोकसभा में कही।

तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद ने बुधवार को सरकार पर संविधान बदलने की कोशिश करने और जानबूझकर विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष पदों को खाली रखने का आरोप लगाते हुए मांग की कि देश में दलितों और पिछड़ों को सामाजिक न्याय देने के लिए इन पदों को जल्द भरा जाना चाहिए। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण और धनगर समुदाय को आरक्षण देने के लिए हो रहे आंदोलनों का समाधान निकालने, जनजातियों को आदिवासी पुकारने और शिक्षा के अधिकार कानून के तहत स्नातक स्तर तक छात्रों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करने समेत विभिन्न मांग बुधवार को लोकसभा में की गईं। शून्यकाल में विभिन्न दलों के सदस्यों ने लोक महत्व के विषय सदन में उठाए।

द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) सांसद दयानिधि मारन ने बुधवार को केंद्र सरकार पर तमिलनाडु और तमिल जनता से भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ''राज्य की जनता भाजपा-नीत सरकार को कभी माफ नहीं करेगी।'' मारन ने केंद्रीय बजट 2024-25 पर लोकसभा में चर्चा में भाग लेते हुए इसमें बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए किए गए बजटीय प्रावधानों का उल्लेख किया और कहा कि सरकार दोनों राज्य की मदद कर रही है, अच्छी बात है लेकिन तमिलनाडु जैसे राज्य को दंडित नहीं किया जाना चाहिए।

बारिश से लबालब हुए डैम, गंगरेल बांध में डेडलाइन से पार हुआ पानी

धमतरी। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाकों में पिछले तीन दिनों से लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश से अब धमतरी के सूखे बांधों में भी पानी की आवक अच्छी खासी होने लगी है। धमतरी के सबसे बड़े गंगरेल बांध में हर घंटे 3 सेंटीमीटर जलस्तर में इजाफा हो रहा है। अब तक बांध में 40 परसेंट से ज्यादा पानी भर चुका है। बारिश लगातार जारी है अच्छे पैमाने पर पानी की आवक भी लगातार हो रही है।

गंगरेल बांध के साथ-साथ जिले के माडमसिल्ली, दुधावा, और सोंढुर बांध में भी जलस्तर काफी हद तक सुधर चुका है। यह एक बड़ी राहत देने वाली खबर है। क्योंकि बीते महीने में ही धमतरी जिले के सभी बांध लगभग सूख चुके थे और हालत चिंता पैदा करने वाले थे। लेकिन जुलाई माह में सावन लगने के बाद पहले सोमवार से ही जो झमाझम बारिश शुरू हुई, उससे 48 घंटे के अंदर ही सभी बांधों की स्थिति खतरे से बाहर हो चुकी है।

कलेक्टर नम्रता गांधी ने कहा पिछले 3- 4 दिनों की बारिश से काफी राहत मिली है। खेती किसानी और बांध के मामले में ये काफी अच्छी बारिश हुई। सभी डैम लगभग 35 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ गए हैं।

32.15 टीएमसी वाले गंगरेल बांध में 15.004 टीएमसी पानी भर गया है। यहां 66 हजार 36 क्यूसेक पानी आ रहा है। अब तक गंगरेल में 40 फीसदी पानी भर चुका है। माडमसिल्ली बांध जो 5.839 टीएमसी वाली क्षमता रखता है जिसमे में 2.790 टीएमसी पानी भर गया है। यहां 15 हजार 682 क्यूसेक पानी आ रहा है। अब तक माडमसिल्ली में 46.66 फीसदी पानी भर गया है। 10.192 टीएमसी वाले दुधावा बांध में 4.112 टीएमसी पानी भर गया है। यहां 5 हजार 194 क्यूसेक पानी आ रहा है। दुधावा बांध में 39 फीसदी पानी भर गया है। 6.995 टीएमसी वाले सोंढूर बांध में 3.44 टीएमसी पानी भर गया है। यहां 3 हजार 565 क्यूसेक पानी आ रहा है. इस तरह सोंदूर में 43.97 फीसदी पानी भर गया है।

उम्मीद है कि यह बारिश इसी तरह दो से तीन दिन और हुई तो सभी बांध लबालब हो जाएंगे। बांधों के भर जाने से किसानों में भी खुशी है। साथ ही जिला प्रशासन भी काफी राहत महसूस कर रहा है। क्योंकि इन बांधों से न सिर्फ सिंचाई होती है। बल्कि रायपुर, धमतरी और भिलाई जैसे शहरों को पीने का पानी भी दिया जाता है। इसके साथ ही भिलाई इस्पात संयंत्र को चलाने के लिए भी गंगरेल बांध से ही पानी दिया जाता है। इस तरह से धमतरी के बांधों के भर जाने से पूरे छत्तीसगढ़ को बड़ी राहत मिली है।

वहीं ज्यादा बारिश से कुछ इलाकों में जलभराव की समस्या भी बनी है। कलेक्टर नम्रता गांधी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों की बारिश से कई जगह जलभराव हुआ लेकिन अब स्थिति कंट्रोल में हो रही है। नगरी में एक बच्ची नाले में बह गई। नगरी में ही कुछ गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटने की स्थिति बन गई थी जो अब काफी हद तक संपर्क में है। राशन की व्यवस्था कराई जा रही है। बारिश के दिनों में बीमारियों का ज्यादा खतरा रहता है ऐसे में पानी उबालकर पीएं। मलेरिया, डेंगू, डायरिया से बचाव करें। कोई भी तकलीफ होने पर अस्पताल तुरंत जाएं।

दुर्ग में बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, बाढ़ में फंसे मजदूर

दुर्ग। दुर्ग में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश से कई जगह पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। चंगोरी गांव में ईट भट्ठा पर काम कर रहे मजदूर और उनके परिवार बाढ़ में फंस गए। जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकला। एसडीआरएफ की टीम ने 12 से अधिक लोगो का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। दुर्ग के शिवनाथ नदी महमरा एनीकट के ऊपर 10 फीट पानी बह रहा है। नदी के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिसे लेकर जिला प्रशासन द्वारा शिवनाथ नदी तट के सभी गांव के लोगों को अलर्ट रहने की हिदायत दी है। शिवनाथ नदी के किनारे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र झोला, भोथली, रूदा, खाड़ा, चंगोरी, थनौद, पीसेगांव, महमरा, पुलगांव, कोसमी, मोहलई, नगपुरा, मालूद, बेलौदी, पीपरछेड़ी, झेंझरी, हटगांव, गनियारी, सहगांव पर जिला प्रशासन अपनी नजर बनाई हुई है। वहीं, राजनांदगांव जिले के मोंगरा बैराज से पिछले दिनों 40 हजार क्यूसेक पानी शिवनाथ नदी में छोड़ा गया था। आज फिर 5 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया। जिससे शिवनाथ नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रही है। बारिश से तांदुला जलाशय में 40 प्रतिशत, खरखरा जलाशय में 43 प्रतिशत, खपरी जलाशय में 42 प्रतिशत और गोंदली जलाशय में 22 प्रतिशत जलभराव हो चुका है।

मूसलाधार बारिश से लोग हुए परेशान, पेड़ गिरने से वाहनों को भी नुकसान

जगदलपुर। बस्तर जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जहाँ निचली बस्तियों में रहने वाले लोग घरों में पानी से बचने के लिए तरह-तरह के जतन कर रहे है। वहीं शहर में एक सप्ताह के अंदर तीन विशालकाय पेड़ भी धराशाही हो चुके हैं। इन पेड़ों के गिरने से काफी नुकसान हुआ है। कोतवाली थाना के अंदर वर्षों पुराना पेड़ अचानक से गिर गया इस पेड़ के नीचे खड़े वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इसके अलावा जिस जगह पेड़ था, वहां की दीवार भी टूट गई। वहीं महादेव घाट रोड पर एक विशालकाय बरगद का पेड़ गिर गया जिसकी सूचना मिलने पर एसडीआरएफ टीम के साथ ही नगर सेना सेनानी संतोष मार्बल उपकरण सहित मौके पर गए जहां टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंच घर पर गिरे बरगद के पेड़ को काटकर अलग किया गया।

विभिन्न वारदातों में शामिल दो नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

सुकमा। जिले में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन एवं पुनर्वास नीति एवं नियद नेल्ला नार योजना तथा अति अंदरूनी क्षेत्रों में लगातार कैम्प स्थापित होने से पुलिस के बढ़ते प्रभाव के परिणम स्वरूप नक्सल संगठन में सक्रिय 2 नक्सलियों माड़वी जोगा कोराजगुड़ा आरपीसी डीएकेएमएस उपाध्यक्ष एवं सवलम पुल्ला ग्राम पालागुड़ा डीएकेएमएस सदस्य ने आज आत्मसमर्पण कर दिया है।

नक्सलियों को आत्मसमर्पण हेतु प्रोत्साहित कराने में नक्सल सेल आसूचना शाखा की टीम व थाना स्टाफ कोंटा का योगदान रहा। दोनों आत्मसमर्पित नक्सली प्रतिबंधित नक्सल में जुडकर विभिन्न नक्सली वारदातों जैसे पुलिस गस्त पार्टी की रेकी कर हमला करना, पुलिस पार्टी के आने-जाने वाले मार्गो में स्पाईक-आईईडी लगाना, मुख्य मार्गों को खोदकर अवरूद्ध करना, शासन-प्रशासन के विरूद्ध में नक्सली पर्चा-पाम्पलेट लगाना आदि वारदातों में शामिल रहे है। उक्त दोनों आत्मसमर्पित नक्सलियों को छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन एवं पुनर्वास नीति के तहत् सहायता राशि व अन्य सुविधायें प्रदाय कराये जायेंगे।

अरनपुर में एक लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार

दंतेवाड़ा। पुलिस ने नीलवाया क्षेत्र के गांव बुरगुम में नक्सली होने की सूचना पुलिस को मिली थी। जिसके बाद डीआरजी बस्तर फाइटर्स की टीम नक्सल गश्त सर्च अभियान और एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई के लिए रवाना हुई। सर्चिंग के दौरान ग्राम बुरगुम के पास एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस बल को देखकर छिपने की कोशिश करने लगा। पुलिस बल ने संदिग्ध व्यक्ति को घेराबंदी करके पकड़ा।जब पुलिस ने संबंधित शख्स से पूछताछ की तो उनके होश उड़ गए।

संदिग्ध से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम आयता मरकाम बुरगुम निवासी नंदापारा थाना अरनपुर होना बताया। टीम ने आयता मरकाम के पकड़े जाने की सूचना अफसरों को दी। इसके बाद डीआरजी दफ्तर में संदेही को लाकर विस्तृत पूछताछ की गई।जिसमें उसने बताया कि वो नक्सली दल का सक्रिय सदस्य है। जो अरनपुर आईईडी ब्लास्ट, विधानसभा चुनाव के दौरान आईईडी लगाना, पुलिस बल पर हमला, ग्रामीणों की जनदालत में हत्या जैसी 08 अपराधों में शामिल रह चुका है।जिसके बाद पुलिस ने नक्सली को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया।जहां से आयता मरकाम को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

लोन वर्राटू अभियान के तहत पांच लाख के इनामी नक्सली हुर्रा कुंजाम ने हथियार डाल दिए। सरेंडर करने वाला इनामी नक्सली कुंजाम पीपीसीएम रैंक के उत्तर सब जोनल ब्यूरो के राजनैतिक टीम का कमांडर था। नक्सली ने सरकार की शुरु की गई। लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का फैसला किया। सरेंडर करने वाला नक्सली लंबे वक्त से नक्सली संगठन से जुड़ा रहा है। दंतेवाड़ा के कई थाना क्षेत्र में वो सक्रिय भी रहा है।

पहाड़ी कोरवा महिला नवजात के साथ अस्पताल से हुई लापता, मचा हड़कंप

कोरबा। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पहाड़ी कोरवा महिला नवजात शिशु सहित बेड से गायब मिली। महिला बिना बताए अस्पताल से कहीं चली गई, उसका कुछ जरूरी जांच किया जाना था। अस्पताल प्रबंधन ने अपने स्तर पर काफी खोजबीन की लेकिन महिला और शिशु नहीं मिले। जिसके बाद इसकी सूचना जिला अस्पताल चौकी पुलिस को दी गई। इस घटना ने अस्पताल प्रबंधन की करोड़ों रुपए की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि सिविल लाइन रामपुर थाना अंतर्गत आछीमार में शिशुपाल पहाड़ी कोरवा निवास करता है। उसकी 23 वर्षी पत्नी सुक्रिता बाई को प्रसव पीड़ा होने पर 17 जुलाई को जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। जहां डॉक्टरों की देखरेख में स्वास्थ्य कर्मियों ने सुरक्षित प्रसव कराया। प्रसव के बाद जच्चा-बच्चा को महिला वार्ड में रखा गया था। दोनों का छुट्टी से पहले कुछ जरूरी जांच किया जाना था। लेकिन सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी गार्ड के सुरक्षा के बीच महिला और शिशु लापता हो गए। स्वास्थ्य कर्मी जब बेड के पास पहुंचे और जच्चा बच्चा को गायब देखा तो उनके होश उड़ गए।

स्वास्थ्य कर्मी अपने स्तर पर पतासाजी करते रहे लेकिन ना तो प्रसूता और ना ही किसी परिजन का पता चल सका।आखिरकार मामले की सूचना प्रबंधन की ओर से जिला अस्पताल पुलिस चौकी को दी गई। इस पूरे मामले में खास बात यह है कि प्रबंधन द्वारा अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचने वाले राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पहाड़ी कोरवा को किसी प्रकार की परेशानी ना हो इसके लिए अलग से हेल्थ डेस्क बनाया गया है। जहां कर्मचारी भी तैनात किए गए हैं, जिन्हें पहाड़ी कोरवाओं के लिए समुचित व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात किए गए हैं इसके बावजूद भी वो लापता हो गई।

भोरमदेव से अमरकंटक तक कांवड़ियों के लिए विशेष इंतजाम

कवर्धा। पवित्र सावन माह के आगमन के साथ ही शिवभक्तों द्वारा अमरकंटक से भोरमदेव मंदिर तक की 150 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री श्री विजय शर्मा के निर्देश पर इस यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि यात्रा में भक्तगणों को दिक्कत न हो।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा के निर्देशानुसार, कांवडियों के लिए 15 से अधिक स्थानों पर चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस पेट्रोलिंग के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। पुलिस अधीक्षकों को सुरक्षा के बेहतर इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें 4 पुलिस पेट्रोलिंग टीमें और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस की ड्यूटी शामिल है। कांवडियों के लिए यात्रा के दौरान 20 से अधिक स्थानों पर ठहरने की विशेष व्यवस्था की गई है। अमरकंटक के मृत्युंजय आश्रम में निःशुल्क भोजन और रात्रि विश्राम की व्यवस्था है। भोजन में दाल-भात, सब्जी, मीठा जैसे खीर, पुड़ी और हलवा शामिल हैं। इस व्यवस्था की निगरानी में बोलबम समन्वय समिति और स्थानीय अधिकारी जुटे हुए हैं।

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के निर्देश पर कांवडियों के लिए विभिन्न स्थानों पर चिकित्सा कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। पदयात्रा के दौरान शांति और सुरक्षा व्यवस्था के लिए पेट्रोलिंग पार्टियों का गठन किया है। कवर्धा से बेमेतरा हाईवे रोड, कवर्धा से भोरमदेव, बोड़ला-पोड़ी-पंडातराई-पंडरिया, और पंडरिया से कुकदूर सरहदी क्षेत्र तक पेट्रोलिंग पार्टियों को तैनात किया गया है। सावन माह के दौरान उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा की पहल और निर्देशों के तहत कांवडियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और ठहरने की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिससे वे बिना किसी कठिनाई के अपनी यात्रा पूरी कर सकें।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

महतारी वन्दनः महिलाओं के सशक्तिकरण की ओर कदम

कोरिया। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल जिला कोरिया में भी महतारी वंदन योजना का सफल क्रियान्वयन हुआ है। ग्राम ऊपर पारा, खरवत में रहने वाली 31 वर्षीय श्रीमती कविता पति विमल कुमार, जो आठवीं तक पढ़ी हैं और तीन बच्चों की मां हैं, इस योजना का लाभ उठाने वालों में से एक हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक उनके खाते में चार किस्त की राशि आ चुकी है। श्रीमती कविता ने कहा कि इस योजना के फार्म भरते समय उन्हें पूरा भरोसा था कि यह राशि उन्हें जरूर मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस राशि से उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कॉपी-पेन खरीदे और घर के लिए राशन व सब्जी भी खरीदी कर रही है। कविता ने विष्णुदेव साय की प्रशंसा करते हुए कहा कि जो सबकी चिंता दूर करें, परेशानियों से निजात दिलाए वही देश, प्रदेश और घर का मुखिया होता है। श्रीमती कविता ने बताया कि राज्य सरकार की इस योजना से वे और उनका परिवार बहुत खुश हैं। निश्चित ही महतारी वन्दन योजना ने महिलाओं को न केवल आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, बल्कि उनके जीवन में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता भी बढ़ाई है।

कच्ची सड़क को लेकर संबलपुर में विरोध प्रदर्शन

कोंडागांव। कोंडागांव जिला मुख्यालय से सटे ग्राम पंचायत संबलपुर के वार्ड क्रमांक 04 बड़े पारा के ग्रामीणों ने कच्ची सड़क की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस इलाके के निवासी सालों से सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं। गर्मी और ठंड के मौसम में किसी तरह गुजर-बसर कर लेते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में कीचड़ और गड्ढों से भरी सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है। स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी इस समस्या से परेशान हैं। कई बार स्लिप होकर गिरने की घटनाएं भी हो चुकी हैं। स्थानीय निवासियों ने सरपंच, सचिव और पंच के सामने कई बार अपनी समस्याएं रखी, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। आखिरकार, हताश होकर ग्रामीणों ने कीचड़ और गड्ढों वाली इस सड़क पर धान का रोपा लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि जब प्रशासन उनकी समस्या का समाधान नहीं कर रहा है, तो इस सड़क पर धान लगाकर कुछ आमदनी तो हो सकती है। इस अनूठे विरोध प्रदर्शन से ग्रामीणों ने अपनी व्यथा को उजागर किया।

कच्चे मकान की दीवार ढहने से एक की मौत, एक घायल

कांकेर। अंतागढ़ थाना क्षेत्र अंर्तगत ग्राम लामकन्हार में एक कच्चे मकान की दीवार ढहने से घर में सो रही एक महिला रामकुंवर उम्र 50 वर्ष की मौत हो गई, वहीं साथ में सो रही उनकी पुत्री डिकेशवरी उम्र 20 वर्ष घायल हो गई है, जिसका उपचार अंतागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतागढ़ से लगे ग्राम लामकन्हार के आवासपारा में मंगलवार रात 10.30 बजे कच्चे मकान की दीवार गिर गई। इस वक्त घर के भीतर सो रही रामकुंवर पति स्व. हरिराम हिचामी उम्र 50 वर्ष की दीवार के मलबे में दबने से मौत हो गई। बगल में सो रही मृतिका की बेटी डिकेशवरी उम्र 20 वर्ष घायल है। घटना की जानकारी पर आस-पास से लोग एकत्र हुए और जैसे-तैसे कर मलबे में दबी महिला और उसकी बेटी को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि रामकुंवर की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। वही घायल बेटी डिकेशवरी को अंतागढ़ अस्पताल इलाज के लिए लाया गया। पुलिस ने कायर्वाही के उपरांत रामकुंवर का पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा दिया गया।

ट्रक और बस में जोरदार भिड़ंत हादसे के बाद मची चीखपुकार

कोरबा। कोरबा में कटघोरा अंबिकापुर नेशनल हाईवे में बुधवार की तड़के सुबह भीषण हादसा हो गया, बताया जा रहा है की यात्री बस जो औरंगाबाद बोधगया से चलकर रायपुर दुर्ग भिलाई के लिए जा रही थी, इस दौरान बागों थाना अंतर्गत मोरगा चौकी के केंदई गांव के पास हाईवे पर खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसे के बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया। कुछ लोगों को मामूली चोट आई है, जिनका मौके पर मौजूद हाईवे एंबुलेंस की मदद से घटनास्थल पर ही प्राथमिक उपचार किया गया। घटनास्थल पर बारिश और हाथी प्रभावित क्षेत्र होने के कारण सभी यात्रियों को डायल 112 वाहन एवं हाईवे एंबुलेंस की मदद से सुरक्षित स्थान पर लाया गया। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर डायल 112 में तैनात आरक्षक रामसिंह और चालक नीरज पांडेय ने बड़ी सुझबुझ के साथ यात्रियों को दूसरी बस की मदद से उनके गंतव्य स्थान के लिए रवाना किया गया।

जमीन पर सोई दो सगी बहनों को करैत सांप ने डसा

जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम भैसो की आश्रित गांव डूमरपाली में जमीन पर सो रही दो सगी बहनों की जहरीले सांप करैत के काटने से मौत हुई है। घटना के बाद परिवार में मातम पसर गया। ये मामला जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार अनन्य जांगडे 16 वर्ष और दीप्ति जांगडे 19 वर्ष दोनों मंगलवार की रात खाना खाने के बाद जमीन पर सोई हुई थी तभी करैत सांप ने बारी बारी से दोनों को डस लिया। रात 11 बजे दोनों को उल्टी होने लगी, तभी परिजनों ने दोनों को उपचार के लिए पामगढ़ सीएचसी लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने छोटी बहन अनन्य जांगडे को मृत घोषित कर दिया। वहीं बड़ी बहन दीप्ति जांगडे को उपचार के लिए बिलासपुर रेफर किया लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले उसने भी रास्ते में दम तोड़ दिया। घटना की सूचना पामगढ़ पुलिस को मिलने पर अस्पताल पहुंची और दोनों के शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है।

केंद्रीय बजट में कैपिटल गेन टैक्सेशन में बड़ा बदलाव

प्रॉपर्टी बेचने पर अब लगेगी टैक्स की मार, इंडेक्सेशन का लाभ अब नहीं मिलेगा

भाटापारा। अगर आप प्रॉपर्टी या शेयर बाजार, कहीं भी निवेश किया है या निवेश करना चाहते हैं तो इस बजट में हुए बदलाव आप के लिये जानना बहुत ज़रूरी है। सरकार ने इस बजट में कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव का ऐलान किया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट रूचि अग्रवाल ने बताया कि आसान भाषा में समझें तो कैपिटेल गेन टैक्स यानी की आपके मुनाफे पर लगने वाला टैक्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में लॉन्ग टर्म की परिभाषा को भी स्पष्ट किया।

उन्होंने कहा कि जो लिस्टेड फाइनेंशियल एसेट्स हैं, उन्हें एक साल या उससे अधिक समय तक होल्ड करने पर ही लॉन्ग टर्म निवेश माना जाएगा। इसमें शेयर, म्यूचअल फंड भी आएंगे। वहीं, अनलिस्टेड फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल दोनों एसेट्स को अगर 2 साल या उससे अधिक होल्ड किया जाता है तो उसे लॉन्ग टर्म निवेश माना जाएगा। वित्त मंत्री ने इस बजट में पूंजीगत लाभ (कैपिटेल गेन) टैक्स में बड़े बदलावों की घोषणा की है, साथ ही इंडेक्सेशन बेनेफिट के नियम को हटा दिया जिसका असर मुख्य रूप से रियल एस्टेट लेनदेन को प्रभावित कर सकता है। संपत्ति की बिक्री पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (एलटीसीजी) 20 से घटाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया है। पहली नजर में आपको लगेगा कि सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटेल गेन टैक्स को कम कर दिया है.लेकिन ऐसा नहीं हैं । दरअसल, प्रॉपर्टी बेचने पर अब तक जो इंडेक्सेशन बेनेफिट मिलता था उसे इस बजट में हटा दिया गया है। इंडेक्सेशन बेनेफिट में आपकी प्रॉपर्टी की महंगाई दर के हिसाब से नई कीमत निकाली जाती थी, उसके बाद जो रकम बचती थी उस पर 20 फीसदी टैक्स लगता था। लेकिन अब इसे बदल दिया गया है।

चार्टर्ड अकाउंटेंट रूचि अग्रवाल ने इसे समझाते हुए बताया कि उदाहरण के तौर पर दस साल पहले अगर आप कोई प्रॉपर्टी 25 लाख की खरीदी थी तो आज उसका कीमत 1 करोड़ हो गई होगी। अब ऐसे में अगर आप इस प्रॉपर्टी को बेचेंगे तो पहले के नियम के अनुसार इस पर इंडेक्सेशन बेनेफिट लागू होता। यानी महंगाई को ध्यान में रखकर आपके 25 लाख की नई वैल्यू लगाई जाती। अब मान लीजिए की इण्डेक्सेशन के हिसाब से आज आपके जमीन की कीमत 80 लाख है तो आपके जमीन की कीमत 80 लाख मान ली जाती.फिर नियम के अनुसार आपके 20 लाख रुपये पर 20 फीसदी की दर से लॉन्ग टर्म गेन टैक्स लगता। लेकिन अब इस नियम को हटा दिया गया है।

नये नियम के अनुसार अब आपको पूरे 75 लाख पे 12.5 प्रतिशत के दर से टैक्स का भुक्तान करना पड़ेगा। सरकार के इस फैसले से प्रॉपर्टी बेचने वालों को भारी टैक्स का झटका लग सकता है।

सीआरपीएफ जवानों ने प्रसूता और नवजात बच्चे को उफनती नदी से कराया पार

बस्तर। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग इन दिनों अच्छी बारिश हो रही जिसके चलते नदी नाले उफान पर है। संभाग के कई गांवों का शहरों से संपर्क टूच गया है। ऐसे में ग्रामीणों को कई जरूरी सुविधाओं के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच उसूर इलाके में सीआरपीएफ के जवानों ने उफनती नदी से प्रसूता और नवजात को सुरक्षित पार करा कर एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की है।

दरअसल, नम्बी गांव के नयापारा निवासी महिला माड़वी जागी को अचानक दर्द उठा और समय से पूर्व ही उसने बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद जच्चा और बच्चा दोनों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उसूर जाना था, लेकिन रास्ते में पड़ने वाली नम्बीधारा नदी तेज उफान पर थी। ऐसे में सीआरपीएफ की 196 वीं बटालियन और कोबरा 205 बटालियन के जवानों ने प्रसूता और बच्चे की गंभीर स्थिति को समझते हुए उनको कड़ी मशक्कत कर सुरक्षित नदी पार कराया। जवानों ने प्रसूता और नवजात को जुगाड़ का सहारा लेकर नदी पार कराया। उन्होंने प्लास्टिक के ड्रम और लकड़ी से नाव तैयार की और रस्सी के सहारे पानी में उतरे। नदी के तेज बहाव के बीच घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार जवानों ने प्रसूता और नवजात बच्चे को नदी से सुरक्षित पार कराया। उनकी तत्परता और जज्बे की वजह से अब नवजात शिशु और महिला दोनों सुरक्षित हैं। बता दें, इंसानियत की मिशाल पेश करने वाले ये जवान नक्सल मोर्चा पर तैनात थे। समय समय पर सुरक्षाबल के जवान मूसीबत में फंसे लोगों की मदद करते हैं। पिछले साल भी सीआरपीएफ के जवानों ने बीजापुर में आई बाढ़ में फंसे ग्रामीणों की जान बचाई थी। घटना की वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और लोग जवानों के जज्बे को सलाम कर रहे हैं।

संक्षिप्त समाचार

प्रवीण कुमार यादव ने अपनी पीएच.डी. डिग्री प्राप्त की

रायपुर। पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा श्री प्रवीण कुमार यादव को कला सकांय के अंतर्गत हिन्दी विषय में समकालीन हिन्दी कवयित्रियों में प्रतिरोध के स्वर विषय पर पी-एच.डी. की उपाधि प्रदान की। उन्होंने अपना शोध कार्य रायपुर की शासकीय नवीन महाविद्यालय गुढियारी की सहायक प्राध्यापिका डॉ. वंदना कुमार के निर्देशन में पूर्ण किया। उनका शोध केन्द्र संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कुरूद, जिला धमतरी था। उनके को-गाइड डॉ. प्रभात रंजन सहायक प्राध्यापक हिन्दी शासकीय वीर सुरेन्द्र साय महाविद्यालय गरियाबंद थे। गौरतलब है कि समकालीन हिन्दी कवयित्रियों में प्रतिरोध के स्वर पर इससे पहले कोई शोध कार्य नहीं हुआ था। यह उनका पहला कार्य है। डॉ. प्रवीण कुमार यादव विगत 17 वर्षों से विभिन्न महाविद्यालयों में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्य किया है। वर्तमान में वे प्रगति कॉलेज के जनसंचार विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। साथ ही वे स्वतंत्र पत्रकार के रूप में विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं के लिए निरंतर लेखन कार्य करते रहें हैं।

बिजली उपभोक्ताओं की बढ़ी परेशानी, नहीं हो रहा 5000 से अधिक का कैश भुगतान

रायपुर। राजधानी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए अब एक नई परेशानी का समाना करना पड़ रहा है। जिसकी वजह से वह बिजली ऑफिस का चक्कर काट कर वापस घर जा रहे हैं। दरअसल, मामला यह है कि उपभोक्ता 5000 से ज्यादा का बिजली बिल जमा करने जा रहे हैं तो वे भुगतान नहीं कर पा रहे है। उपभोक्ता न तो कैश और न नहीं डिजिटल पेमेंट कर पा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि उनसे विद्युत दफ्तर में बैठे अधिकारी-कर्मचारी भुगतान नहीं ले रहे हैं। जिसकी वजह से उन्हें मायूस होकर जाना पड़ रहा है। ऐसा उपभोक्ताओं के साथ क्यों हो रहा है इसकी सही से जानकारी भी नहीं दी जा रही है। न ही उन्हें बताया जा रहा है कि वे बिजली बिल का भुगतान कैसे कर सकते हैं। रायपुर के एक बिजली दफ्तर के गेट के बाहर तख्ती भी लगाया गया है। जिसमें लिखा गया है कि विद्युत देयक नगद राशि 5000 रुपये से अधिक की राशि स्वीकार नहीं की जावेगी।

युवाओं के लिए नए अवसर-नई ऊर्जा का बजट : संजय जोशी

रायपुर। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट युवाओं पर फोकस है।यह युवाओं को एक नई ऊर्जा एवं नए अवसर देने वाला बजट है।छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के पूर्व सदस्य एवं शिक्षाविद संजय जोशी ने भारत सरकार के बजट को शैक्षणिक गुणवत्ता एवं युवाओं के लिए एक उपयोगी एवं सार्थक बजट बताया है। संजय जोशी ने कहा कि प्रतिवर्ष 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के लिए एक वर्ष तक प्रति माह 5 हजार रुपये देने का अभूतपूर्व निर्णय शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों में आकर्षण एवं उन्हें स्किल बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। 3 प्रश ब्याज में छूट के साथ 10 लाख तक उच्च शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन की घोषणा विद्यार्थियों को राहत प्रदान करेगी। देश के सभी आईटीआई को आधुनिक बनाने की घोषणा आज के समय की आवश्यकता को पूरा करने एवं युवाओं को रोजगार के नए अवसर देगी।वर्ष 2023 में एजुकेशन सेक्टर में 1.12 लाख करोड़ के बजट मे ऐतिहासिक वृद्धि करते हुए इस वर्ष 2024 में इसे 1.48 लाख करोड़ करना केन्द्र सरकार की एजुकेशन के प्रति इच्छाशक्ति को प्रदर्शित करता है। यह केंद्रीय बजट देश के विद्यार्थियों एवं युवाओं के सपनों को पंख देगा।

सीएम विष्णु के सुशासन में एक कॉल पर हो रहा समस्या का निराकरण

रायपुर । मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन में एक फोन कॉल पर समस्याओं का त्वरित निराकरण हो रहा है। जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए जनसमस्या निवारण कॉल सेंटर में रायपुरा के सांई मंदिर के पास बिजली खंबे से चिंगारी निकल रही थी, तभी नागरिकों ने कोई अनहोनी न हो, इसके पूर्व कॉल सेंटर में फोन घुमाया। इसके बाद तुरंत शिकायत दर्ज की गई और बिजली विभाग के अधिकारियों को तुरंत जानकारी दी गई। इसके तत्पश्चात बिजली विभाग के कर्मचारी मौके के लिए रवाना हुए और तुरंत बिजली खंभे में मरम्मत का कार्य प्रारंभ किया गया। रहवासी कॉलोनी में अचानक बिजली खंभे से चिंगारी निकलने लगी। तभी कॉलोनी के नागरिकों ने जनसमस्या निवारण कॉल सेंटर में फोन किया। खंबे में लगे हुए स्ट्रीट लाइट फीटिंग में माइनर स्पार्किंग हो रही थी, जिसे कर्मचारियों ने सुधार किया। बिजली अमला ने कुछ देर में ही समस्या का निराकरण कर दिया। इस त्वरित कार्य की नागरिकों ने सराहाना की और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद ज्ञापित किया।

25 जुलाई को होने वाला जनदर्शन स्थगित

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का हर सप्ताह गुरुवार को होने वाला जनदर्शन इस गुरूवार 25 जुलाई को छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के मद्देनजर नहीं होगा।

नक्सलवाद पर विधानसभा में हंगामा, महंत का गृह मंत्री से सवाल

■ **मुठभेड़ में निर्दोष आदिवासियों की हत्या का लगाया आरोप**

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में उस समय हंगामा हो गया जब नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने नक्सलियों से जुड़ा प्रश्न सदन में पूछा। महंत ने पूछा कि दिसंबर 2023 से जून 2024 तक प्रदेश में नक्सली घटनाओं में कितने जवान शहीद हुए और कितने आम लोग मारे गए। क्या गोली से मारे गए या गला काटकर 34 आम लोगों की हत्या की गई।

डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने पहले कहा कि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की बातें गुगली बॉल की तरह होती है इसलिए मैं शुरू से ही चिंतित था। लेकिन ये विषय स्पष्टता के साथ सदन में रखना चाहिए। शर्मा ने कहा- प्रदेश में नक्सल घटनाओं की संख्या 273 है और 92 घटनाओं में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुए हैं। पुलिस जवान शहीद हुए हैं। 88 जवान घायल हुए जो अब स्वस्थ है। 34 आम लोगों की हत्या की गई। इसमें 4 ऐसे है जिन्हें नक्सलियों ने जनअदालत लगाकर मार डाला। आईईडी ब्लास्ट में कई लोग मारे गए। मुखबिरी के आरोप में 24 लोगों की हत्या नक्सलियों ने की। नक्सलियों की फायरिंग में 1 की मौत हुई।

चरणदास महंत ने आगे पूछा- मारे गए 137 नक्सलियों और गिरफ्तार किए गए 401 नक्सलियों में कितने नक्सली छत्तीसगढ़ के थे, कितने इनामी नक्सली थे कितने बाहरी थे और कितने छत्तीसगढ़ के थे।

शर्मा ने इसका जवाब देते हुए कहा कि- स्टेट जोनल कमेटी मेंबर के दो ऐसे नक्सली थे जिन पर 25 लाख का इनाम था। डिविजनल कमेटी मेंबर 6 नक्सली है जिन पर 8 लाख का इनाम था, कंपनी सदस्य 13 है जिन पर 8 लाख का इनाम था। कंपनी डिप्टी कमांडर 1 जिस पर 8 लाख का इनाम था। कंपनी स्नाइपर कमांडर 8 लाख का इनाम था। स्मॉल एक्शन कमेटी के सदस्य पर 8 लाख का इनाम था। एरिया कमेटी के 22 नक्सलियों पर 5-5 लाख का इनाम था। एलजीएल के कमांडर पर 5 लाख का इनाम, प्लाटून सेक्शन कमांडर 3 लाख का इनाम, सब जोनल एंटी सदस्य 3 लाख का इनाम था। प्लाटून कमांडर 2-2 लाख का इनाम, मिलिशिया कमांडर पर 1 लाख का इनाम। इस तरह से 137 नक्सलियों पर इनाम था जो अभियान के दौरान मारे गए।

चरणदास महंत ने कहा कि इसमें बाहरी कितने थे और छत्तीसगढ़ के कितने नक्सली थे। इस प्रश्न पर शर्मा ने कहा- इसका कैटेगिरजाइशन नहीं किया गया। इसकी जानकारी दे दी जाएगी।

नेता प्रतिपक्ष ने अगला सवाल किया कि इस अभियान में जितने भी हथियार बरामद हुए हैं। उसमें भरमार बंदूकों की संख्या ज्यादा है। आपने कभी इसकी जांच कराई कि भरमार बंदूक चलते है या नहीं क्या इसकी जांच कराई है। शर्मा ने जवाब दिया कि मुठभेड़ के बाद जो बंदूक बरामद किए गए वो जब्त कर मालखाने में रखा गया है। आप देख सकते हैं मैं भी चलूंगा संशय किस बात की है। इस पर महंत ने कहा कि जब भी नक्सली मरता है या गांव वाला मरता है तो भरमार बंदूक बरामद होता है। अब तक कितने भरमार बंदूक जब्त हुए, क्या उसी भरमार बंदूक को लेकर जब्त किया जाता है। क्या आपने एक भी भरमार बंदूक से फायरिंग करते देखा है। 1947 से पहले भरमार बंदूक पहले कितने चलते थे अब कितने चलते हैं। मेरी शंका है कि पुलिस वाले भरमार बंदूक लेकर जाते हैं। बॉडी के साथ भरमार बंदूक रखा जाता है। भरमार बंदूक जब्त हो जाता है और वह नक्सली हो जाता है। इसी तरह आपने कई आम लोगों को नक्सली बनाया है। इसकी जानकारी दीजिए।

शर्मा ने जवाब दिया कि कोई खत्म हो गया और उसके पास रखकर फोटो ले लिए,ये बात अस्वीकारणीय है। ये कहना उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ में नक्सली मुठभेड़ में 1 दिसंबर से 30 जून तक पांच एके 47 बरामद हुए हैं। एलएसआर एलएमजी 1, इनसास एलएमजी 1, रायफल 2, इनसास रायफल 4 इसके साथ कई हथियार बरामद हुए हैं। महंत ने आगे कहा कि 1995 में मैं मध्य प्रदेश में गृहमंत्री था, उस दौरान कभी भरमार बंदूक कभी जब्त नहीं हुआ। क्या जब्त भरमार बंदूक की जांच कराएंगे। इसमें आप उत्तर नहीं दे पाएंगे।

महंत ने आगे पूछा 790 नक्सली जेल में है। 25 सजा प्राप्त है और 765 विचाराधीन है। इनका प्रकरण कब से विचाराधीन है। इस पर विजय शर्मा ने कहा कि महंतजी आप काफी सीनियर है। आपसे निवेदन है कि बाकी की जो चीजें भी बरामद हुई है उस पर भी ध्यान दें। आपने जो प्रश्न किया उसमें पूछा कि कौन कौन सी सामग्री बरामद हुई और कहां रखी गई है। सबका जवाब नेता प्रतिपक्ष को दिया गया है। जितनी भी घटनाएं हुई है जो लोग मारे गए हैं, ऐसी एक भी घटना नहीं कि जिन्हें हमने नक्सली घोषित किया है, और वो नक्सली ना हो। भरमार बंदूक का मिलना, नहीं मिलना शंका का विषय नहीं है। 765 विचाराधीन नक्सली कब से जेल में इसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी।

विधायक विक्रम मंडावी ने चर्चा के बीच में कहा कि बीजापुर के पीडिया गांव में मुठभेड़ होती है। बताया जाता है कि 600 जवान ऑपरेशन करते हैं और 11 नक्सलियों को मारते हैं। वहां 10 भरमार बंदूक मिलते हैं। पूछना चाहता हूं कि 10 भरमार बंदूकों से क्या 600 जवानों का मुकाबला हो सकता है। हम खुद उस गांव में गए। वहां पूछताछ में पता चला कि जो 10 लोग मार गए वो गांव के लोग थे। उनकी पत्नियों ने ये बात बताई। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। नरपल्ली गांव में 110 घर है। जहां से 95 लोगों को पकड़कर लाए गए। इस तरह से नक्सल क्षेत्रों में किया जा रहा है। फर्जी मुठभेड़ कर भरमार बंदूक रखने का काम किया जा रहा है।

विजय शर्मा ने कहा ये मामला पहले भी उठाया गया तब पूरी जानकारी दी गई। 60 हजार, 70 हजार है अब तक नक्सली खत्म नहीं हुए। आपने भी सरकार चलाई है तो क्या नक्सलवाद खत्म हो गया। मंडावी ने कहा आपकी सरकार ने नक्सलवाद खत्म करने का दावा किया है। इस पर विजय शर्मा ने आगे कहा- पीडिया एनकाउंटर के बारे में कुछ बातें सामने आई है जिसमें पता चला है कि बुद्धु ओयाम में साल 2021 में आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज था, कल्लू ऊर्फ छोटू पर साल 2022 में अपहरण का केस दर्ज हुआ। लक्की कुंजाम में 2022 और 2023 में 307 का केस दर्ज है। इस दौरान प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। इस केस में मजिस्ट्रीयल जांच की बात हुई है वह भी हो जाएगी। इस तरह आरोप लगाकर सुरक्षा बलों के मनोबल को मत तोड़िए।

चरणदास महंत ने कहा कि सुरक्षाबलों पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगाया है। गृहमंत्री ने कहा कि नक्सलियों से बात करेंगे। 7 महीने होने वाले हैं आप लोगों ने नक्सलियों से बात करने की कौन सी कोशिश की है। इस सवाल पर विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा कि ये संवेदनशील विषय है इस पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं हो सकती, आप खुद तो गृह मंत्री रह चुके हैं। कवासी लखमा ने कहा पीडिया में अब भी लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्या शासन की तरफ से कभी कोई नेता उनका हालचाल जानने पहुंचा। तेंदूपत्ता तोड़ने वाले लोगों को घेर कर उन्हें गोली मार दी गई। इस पर विजय शर्मा नाराज हो गए और कहा ये बात गलत है। इसके बाद सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर हंगामा हो गया। विपक्ष के नेता सदन में आदिवासियों की हत्या बंद करो के नारे लगाने लगे।

प्रदेश में नौकरी का सुनहरा अवसर, 10 हजार से ज्यादा वैकेंसी

■ **डॉक्टरों की भी बल्ले बल्ले**

रायपुर। मानसून सत्र के तीसरे दिन विधायक भैया लाल राजवाड़े ने प्रश्न पूछा कि बैकुंठपुर जिला अस्पताल में कितने सेटअप है। कौन कौन से पद रिक्त है कौन भरे हैं। वर्तमान में किन पदों पर स्टाफ की जरूरत है। पिछले 2 साल में कितने मरीज अस्पताल में एडमिट किए गए और कितने मरीज रेफर किए गए।

भैया लाल राजवाड़े के प्रश्न का जवाब देते हुए मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पहले विधायक भैया लाल राजवाड़े को अपना अभिभावक बताया। आगे उन्होंने कहा कि बैकुंठपुर जिला अस्पताल में 188 पद स्वीकृत है। 111 लोग काम कर रहे हैं। 77 पद खाली है। 98 पद जीवनदीप समिति, डीएमएफ और एनएचएम से भर लिए गए हैं लेकिन विशेषज्ञ डॉक्टरों के 6 पद खाली है और 9 चिकित्सा अधिकारी के पद खाली है। साल 2022-23 में बैकुंठपुर जिला अस्पताल में 19821 मरीज भर्ती हुए। 1410 को रेफर किए गए। इस वित्तीय वर्ष में 5318 मरीज भर्ती हुए। जिसमें से 481 मरीजों को रेफर किया गया। भइया लाल राजवाड़े ने आगे पूछा कि अस्पतालों से रेफरल कब तक खत्म होगा। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जवाब दिया कि अस्पतालों में डॉक्टरों की भर्ती जल्द होगी। इस पर विधायक अजय चंद्राकर ने टोका और कहा कि विधानसभा में जो घोषणा की जाती है उन्हें पूरा करना भी जरूरी होता है।

विधायक भैया लाल राजवाड़े ने कहा घरों में कई डॉक्टरों ने दुकान लगा रखी है, जिससे डॉक्टर सिर्फ अपने क्लीनिक में बैठे रहते हैं। अस्पताल में दूसरे शिफ्ट में कोई डॉक्टर ही नहीं रहता। डॉक्टरों की दुकान कब तक बंद होगी। डिलीवरी के लिए 50 हजार रुपये लिए जाते हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब दिया कि दो प्रकार के डॉक्टर होते हैं। पहले प्रैक्टिशनर होते है और दूसरे नॉन प्रैक्टिश करने वाले डॉक्टर है। महिला चिकित्सा की नियुक्ति की गई थी, सर्जन भी नियुक्त किया गया था लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। 15 दिन के अंदर जल्द से जल्द महिला डॉक्टर और एनेसथीसिया के डॉक्टरों की भर्ती होगी। 15 दिन के अंदर महिला डॉक्टर और एनेसथीसिया के डॉक्टर की भर्ती होगी।

नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने विधायक को अपना गुरु बताया तो क्या ये मामला कोरिया जिले में ही रहकर इस मामले को क्यों नहीं सुलझाया गया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने भी कहा कि यहां तक मामला नहीं आना चाहिए।

विधायक धरमजीत ने कहा कि पूरे प्रदेश में डॉक्टरों की कमी बनी हुई है। बड़े बड़े लोगों के बच्चे बॉन्ड भरकर सरकारी खर्चे में डॉक्टर बन जाते हैं और फिर पैसे पटा कर छोड़ देते हैं। इस पर कड़ा निर्णय की जरूरत है। मंत्री ने जवाब दिया कि 1079 डॉक्टरों की विशेषज्ञ और मेडिकल अफसरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। 8084 स्टाफ नर्स और भृत्य की भर्ती की जा रही है। 232 प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसियोटेट प्रोफेसर की भर्ती के लिए पीएससी को भेज दिया गया है। इस साल 10 हजार मेडिकल स्टाफ की भर्ती की तैयारी है।

विधायक गजेंद्र यादव ने सवाल किया कि दुर्ग जिला अस्पताल में पिछले 2 साल में कितने प्रसव किए गए जिसमें महिलाओं के टांके खुलने की शिकायत की गई। इस लापरवाही पर क्या कार्रवाई की गई।

मंत्री ने जवाब दिया कि दुर्ग जिला अस्पताल में पिछले 2 साल में 6202 सर्जरी की गई। इसमें 16 मरीजों के टांके खुलने की शिकायत मिली थी जिन्हें दोबारा टांका लगाकर ठीक कर दिया गया। पिछले 6 महीने से ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली। गजेंद्र यादव ने कहा कि 15 दिन पहले भी इस तरह की शिकायत अस्पताल से आई थी। दुर्ग जिला अस्पताल से लगातार ये शिकायत आ रही है इस लापरवाही पर क्या करेंगे। जिला अस्पताल में स्टाफ की समस्या बनी हुई है। जीवन दीप समिति की तरफ से 10 रुपये की राशि लेकर लोगों को बड़ी सहायता मिलती थी। क्या इसे दोबारा शुरू किया जाएगा। इस पर मंत्री ने कहा कि ये कमिटी पर छोड़ा गया है ये जीवनदीप समिति पर निर्भर है।

नेता-प्रतिपक्ष ने सदन में दिखाया पीडीएस दुकानों से बांटा जा रहा घटिया चना

रायपुर। प्रदेश के शासकीय राशन दुकानों से घटिया चना वितरण की जांच की जाएगी। इस बात की घोषणा खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने नेता प्रतिपक्ष डॉ। चरणदास महंत के ध्यानाकर्षण के दौरान मुद्दा उठाए जाने पर की। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने ध्यानाकर्षण के दौरान सदन में शासकीय राशन दुकानों से घटिया चना वितरण का मुद्दा उठाते हुए घटिया चना का सैंपल दिखाया। इसके साथ ही उन्होंने खाद्य मंत्री से घटिया चना की जांच करने की मांग की। मांग को स्वीकार करते हुए कहा कि चना बदला गया या नहीं, उसकी जांच होगी।

डॉ. महंत ने बताया कि कई जिलों में घटिया चना बांटा गया। चना उठाव के बाद उसे घटिया चना से बदला गया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरे प्रकरण की विधायक दल से जांच की मांग की।

वित्त मंत्री की पहल से 3.14 करोड़ के सड़कों के काम स्वीकृत

■ **रायगढ़ में अधोसंरचना विकास को तेजी से दिया जा रहा मूर्त रूप**

रायपुर। प्रदेश के वित्त मंत्री व रायगढ़ विधायक श्री ओ.पी.चौधरी की पहल से रायगढ़ शहर में सड़कों के निर्माण के 3.14 करोड़ की स्वीकृति नगरीय प्रशासन विभाग से मिली है। वित्त मंत्री श्री ओ.पी.चौधरी ने रायगढ़ के जनप्रतिनिधियों और शहरवासियों की मांग को पत्र लिखकर नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरूण साव के समक्ष रखा था, जिसे स्वीकृति प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय प्रदेश के विकास के लिए कृत संकल्पित हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए त्वरित निर्णय लेकर कार्य कराए जा रहे है, जिसके फलस्वरूप प्रदेश के नगरीय निकायों को राष्ट्रीय स्तर पर 5 पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वित्त मंत्री श्री ओ.पी चौधरी की पहल पर रायगढ़ शहर के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूरा किया जा रहा है। शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और मूलभूत सुविधाओं को बेहतर करने की दिशा में निरंतर कार्य हो रहा है। वित्त मंत्री श्री चौधरी के निर्देश पर शहर में डामरीकृत सड़कों के निर्माण पर फोकस किया है, जिससे शहर के भीतर लोगों को आवागमन के लिए सुंदर और सुगम सड़कें मिलें। इसके साथ ही रायगढ़ में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही शिक्षा और खेल के क्षेत्र में भी अधोसंरचना विकास को तेजी से मूर्त रूप दिया जा रहा है। जिससे शहर में सभी वर्गों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाएं जल्द विकसित की जा सके। जिन सड़कों के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है वे डामरीकृत सड़कें होंगी। इसमें 1 करोड़ 8 लाख 42 हजार की लागत से वार्ड क्रमांक 21 सर्किट हाऊस से हाऊसिंग बोर्ड तक बीटी रोड, इसी तरह वार्ड क्रमांक 27 अतरमुड़ा से मंगल भवन तक बीटी रोड निर्माण कार्य के लिए 83 लाख 51 हजार रुपये, वार्ड क्रमांक 32 सर्वेश्वरी स्कूल से 25 एमएलडी एसटीपी प्लांट एवं गीता ट्रेडर्स से बांझीनपाली तक बीटी रोड निर्माण कार्य के लिए 78 लाख 53 हजार रुपये एवं वार्ड क्रमांक 17 हण्डी चौक से अनाथालय होते हुए नीलांचल भवन तक एवं गणेश मंदिर होते हुए बस स्टैण्ड तक बीटी रोड रिपेयरिंग कार्य हेतु 44 लाख 12 हजार रुपये शामिल है।

प्रदेश के 749 शासकीय डॉक्टर में से 131 कर रहे हैं निजी चिकित्सालय या क्लीनिक का संचालन

रायपुर। पूरे प्रदेश में 749 डॉक्टर अपने नियुक्ति दिनांक से आज तक एक ही स्थान पर बने हुए हैं जिनमें से 131 डॉक्टर निजी चिकित्सालय व क्लीनिक का संचालन कर रहे हैं। यह जानकारी तारांकित प्रश्नकाल के दौरान विधायक विनायक गोयल के द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विधानसभा में दिए।

विनायक गोयल ने स्वास्थ्य मंत्री से जानना चाहता कि प्रदेश में कितने ऐसे डॉक्टर हैं जो चिकित्सा महाविद्यालय एवं जिला चिकित्सालय में अपनी प्रथम नियुक्ति दिनांक से लेकर आज तक एक ही स्थान पर पदस्थ हैं और साथ में अपने निजी चिकित्सालय या क्लीनिक का संचालन भी कर रहे हैं? स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 749 डॉक्टर अपनी प्रथम नियुक्ति दिनांक से लेकर आज तक एक ही स्थान पर पदस्थ है एवं इनमें से 131 डॉक्टर निजी चिकित्सालय या क्लीनिक का संचालन कर रहे है। गोयल ने फिर पूछा कि क्या चिकित्सा महाविद्यालय एवं जिला चिकित्सालयों में भारत सरकार द्वारा संचालित आयुष्मान योजना का प्रबंधन एवं वित्तीय प्रभार संविदा कर्मचारियों को दिया जा सकता है? यदि हां तो कहां-कहां दिया गया है? मंत्री जायसवाल ने बताया कि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालयों में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को आयुष्मान योजना का प्रबंधन एवं वित्तीय प्रभार नहीं दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने 13 नगरीय निकायों में लाइब्रेरी की दी सौगात

85 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत, युवाओं को मिलेगा उच्च गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री

■ **ज्ञान आधारित समाज के प्रतीक के रूप स्थापित करने की योजना**

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 13 नगरीय निकायों में लाइब्रेरी निर्माण के प्रस्ताव को वित्त विभाग से हरी झंडी मिल गई है। लाइब्रेरी को नॉलेज बेस्ड सोसायटी यानी ज्ञान आधारित समाज%% के प्रतीक के रूप में प्रदेश के अलग-अलग स्थानों में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने संकल्पित है। उन्होंने आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लाइब्रेरी की सौगात दी है, जिसका लाभ युवाओं को मिलेगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रदेश के युवाओं को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। वित्त विभाग ने रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 13 नगरीय निकायों में लाइब्रेरी के लिए 85 करोड़ 42 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। प्रदेश के 4 नगरीय निकायों में 500 सीटर और 9 नगरीय निकायों में 200 सीटर लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि यह उन विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होगा, जो छोटे शहरों में रहकर उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। लाइब्रेरी निर्माण का मुख्य उद्देश्य स्थानीय युवाओं के शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास को सुनिश्चित करना है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने मुख्य बजट भाषण में भी इसका जिक्र करते हुए कहा था कि युवाओं के अध्ययन के लिए नालंदा परिसर की तर्ज पर लाइब्रेरी निर्माण किया जाएगा। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि इन केंद्रों को नॉलेज बेस्ड सोसायटी यानी ज्ञान आधारित समाज के प्रतीक के रूप में स्थापित किया जाए, ताकि ये युवाओं के लिए प्रेरणा स्त्रोत और सरकार के लिए एक आदर्श बन सके।

कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कांकेर, संबंद्ध चिकित्सालय कांकेर जिला- उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

क्र/सं.सं./भण्डार/2024-25/2663/ कांकेर, दिनांक 22/07/2024

-:: निविदा सूचना ::-

कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कांकेर, संबंद्ध चिकित्सालय कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) की ओर से वर्ष 2024-25 के लिए पैथोलॉजी केमिकल्स, ब्लड बैंक सामग्री एवं अन्य कन्जुमेबल सामग्री एवं एक्स-रे, सी.टी. स्केन, एम.आर.आई फिल्म सामग्री के क्रय हेतु निर्माता कम्पनी तथा उनके अधिकृत विक्रेताओं से मुहरबंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से आवेदन प्रस्तुत कर (जी.एस.टी प्रमाण पत्र सहित) रू. 1000/- (एक हजार रूपये) अधोहस्ताक्षरकर्ता के नाम डी. डी./ बैंकर्स चेक के रुप में मूलत: प्रस्तुत कर अंतिम तिथि को कार्यालयीन दिवस व कार्यालयीन समय में प्राप्त किये जा सकते हैं, कार्यालय द्वारा जारी निविदा प्रपत्र क्रय कर ही निविदा भरी जा सकेगी।

निविदा प्रपत्र बिक्री की अंतिम तिथि - 23/08/2024 अपरान्ह 02:00 बजे तक

निविदा जमा होने की अंतिम तिथि - 23/08/2024 अपरान्ह 03:00 बजे तक

निविदा खोले जाने की तिथि - 23/08/2024 अपरान्ह 4:00 बजे

टीप :- निविदा से संबंधित अन्य जानकारी कार्यालय के भण्डार शाखा से कार्यालयीन दिवस व अवधि में प्राप्त की जा सकेगी।

संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक,
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय,
संबंद्ध चिकित्सालय कांकेर (छ.ग.)

जी-242501298/5

क्या पिछली गलतियां नहीं दोहराएंगे ओली

रंजीत राय

नेपाल में फिर सरकार बदल गई है। यह पिछले दो साल में वहां बनी तीसरी सरकार है। 2015 में नया संविधान लागू होने के बाद से नेपाल में राजनीतिक स्थिरता कायम होने की जो उम्मीद थी, वह गलत साबित हुई। राजनीतिक गठबंधन के सारे संभव स्वरूप आजमाए जा चुके हैं- कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (यूएमएल) और माओवादी, नेपाली कांग्रेस और माओवादी और अब नेपाली कांग्रेस व सीपीएन (यूएमएल)। पुष्प कमल दाहाल उर्फ प्रचंड के नेतृत्व वाली माओवादी पार्टी के पास सिर्फ 32 सीटें हैं और वह तीनों में सबसे छोटी पार्टी है। इसके बावजूद सत्ता का संतुलन बनाए रखने में वह सबसे आगे है। प्रचंड कभी एक तो कभी दूसरे बड़े दल के साथ मिलकर ज्यादातर समय प्रधानमंत्री बने रहे हैं। हालांकि अब नेपाली कांग्रेस और सीपीएन (यूएमएल) के साथ आने के बाद समीकरण बदले नजर आते हैं। नेपाल में यह ऐसा ही है जैसे भारत में भाजपा और कांग्रेस एक साथ आ जाएं। इससे प्रचंड के पांवों तले जमीन खिसक गई है। किसी बड़े जनाधार के अभाव में माओवादियों के लिए अकेले चुनाव लड़ना मुश्किल होगा। देखा जाए तो सीपीएन (यूएमएल) के केपी शर्मा ओली नेपाल के सबसे मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं। बुजुर्ग नेता शेर बहादुर देउबा की अगुआई वाली नेपाली कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद बंटी हुई है। युवा नेतृत्व के अभाव में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जैसी ताकतों से मिल रही चुनौतियों से निपटना उसके लिए मुश्किल साबित हो रहा है। माना जा रहा है कि डेढ़ साल बाद ओली की जगह देउबा को पीएम बनाने की बात तय हुई है। लेकिन नेपाल में इस तरह के वादे अक्सर तोड़े जाते रहे हैं। अगर ओली छोटे-छोटे वाम दलों के सांसदों को अपनी ओर मिला लें तो यूएमएल नेपाल की सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। वैसे भी नेपाली कांग्रेस और यूएमएल में दस सांसदों का ही अंतर है। नेपाल का संविधान कहता है कि अगर कोई सरकार बहुमत खो देती है और कोई नया गठबंधन संभव नहीं होता है तो राष्ट्रपति सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। भारत के लिए जरूरी है कि नेपाल में चाहे जिसकी भी और जैसी भी सरकार बने, उसके साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखे जाएं। लेकिन अतीत में ओली के प्रधानमंत्रित्व काल का अनुभव हमारे लिए अच्छा नहीं रहा है। ओली ने नेपाल में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए भारत विरोधी भावनाओं का इस्तेमाल किया। ओली की पिछली सरकार के कार्यकाल में चीन के साथ ट्रेड, ट्रांजिट और कनेक्टिविटी से जुड़े कई समझौते हुए। भारत के साथ सीमा संबंधी विवाद को भी असामान्य रूप से तूल दे दिया गया। देखने वाली बात होगी कि क्या इस बार ओली सरकार चीन के बेल्ट एंड रोड इनीशटिव (बीआरआई) प्रॉजेक्ट की ओर बढ़ती है। इससे पहले की माओवादी और नेपाली कांग्रेस की अगुआई वाली सरकारों ने इसके साथ रियायती दर पर लोन की शर्त लगा दी थी, जिस पर चीन राजी नहीं था। वैसे भारत के नजरिए से वाम दलों के गठबंधन वाली सरकार के मुकाबले नेपाली कांग्रेस की मौजूदगी वाली सरकार बेहतर है। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में नेपाली कांग्रेस ओली के मनमाने रवैये और एकतरफा फैसलों पर थोड़ा अंकुश लगा सकती है। भारत के लिए सबसे अहम है नेपाल में हाइड्रो पावर और कनेक्टिविटी प्रॉजेक्ट्स पर काम आगे बढ़ता रहे। इनमें से कुछ ने तो अच्छी प्रगति की है, लेकिन 6000+ मेगावॉट के पंचेश्वर प्रॉजेक्ट जैसे कुछ और प्रॉजेक्ट हैं जो अटक गए हैं। मजबूत नेता वाले दो बड़े परस्पर विरोधी विरोधी दलों की सरकार ऐसे मामलों को आगे बढ़ाने के लिहाज से बहुत कारगर साबित हो सकती है। भारत को यह भी देखना होगा कि नई सरकार नेपाल में बढ़ती अमेरिकी-चीनी प्रतिद्वंद्विता से कैसे निपटती है। बहरहाल, नेपाल सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती देश की आर्थिक स्थिति सुधारने की है। यह आज भी अल्पविकसित देश (एलडीसी) की श्रेणी में आता है।

गठबंधन धर्म निभाता आम बजट 2024

कमलेश पांडे

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब 23 जुलाई मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया तो किसी को अमृतकाल और विकसित भारत की आहट मिली, तो किसी को वही रटी रटाई पश्चाताप जो पिछले 10 सालों से होती आई है और अगले 15 सालों तक रहने वाली है, यदि इस बीच गठबंधन की गांठ नहीं खुली तो। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट बताया और कहा कि यह अगले पांच साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला रखेगा। लेकिन उनकी बातों में, बजट अभिभाषण में, और बजट प्रस्तावों में मीन मेख निकालने वाले नेताओं की कमी नहीं दिखी।

बावजूद इसके केंद्रीय बजट 2024 एक संतुलित बजट है, क्योंकि इसमें महिलाओं, युवाओं, गरीबों, किसानों के हित को सामने रखकर विभिन्न आवश्यक व लोकहितकारी घोषणाएं की गई हैं। देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी के अमृत काल वाले विकसित भारत के संकल्प की प्रतिबद्धता को दोहराता हुआ बजट है। जिससे पूरी उम्मीद है कि यह बजट प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के मिशन को पूरा करेगा। वहीं, इस केंद्रीय बजट में क्षेत्रीय असंतुलन को संतुलन में लाने की कोशिश की गई है, जो आगे भी जारी रखी जायेगी, ऐसे संकेत मिले हैं। क्योंकि देश के कुछ पिछड़े क्षेत्र हैं जिन्हें पिछली सरकारों ने नजरअंदाज किया है, इसलिए विकास की गंगा वहां तक पहुंचाना समावेशी विकास की सबसे बड़ी जरूरत है।

शायद इसी नजरिए से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए की गई विभिन्न घोषणाओं से पूर्वी भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इस लिहाज से बजट में 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक का पूंजीगत व्यय आवंटित किया गया है।

केंद्रीय बजट में एक तरफ आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ रुपए और आगामी वर्षों में अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की घोषणा की गई, जो अच्छी बात है। तो दूसरी तरफ बिहार को 26 हजार करोड़ रुपये देने का ऐलान किया गया है। ऐसा करके वित्त मंत्री ने अपने दोनों गठबंधन साथियों टीडीपी और जदयू को साधने की पहल की है, जो समझदारी भरा कदम है। इन दोनों राज्यों के आर्थिक हितों का ख्याल रखने से एनडीए सरकार पांच सालों तक चलती रहेगी और आगे के भी चुनावों में उम्दा प्रदर्शन करती रहेगी।

इस आम बजट को युवाओं और महिलाओं के सपनों का बजट भी करार दिया गया है। क्योंकि इनके दृष्टिगत कौशल विकास और रोजगार सृजन की जो घोषणाएं हुई हैं, वह ऐतिहासिक हैं। इस प्रकार इस बजट में पीएम मोदी का विकसित भारत का सपना पूरी तरह से झलकता है। वहीं, अगर विपक्ष ने इस बजट की आलोचना की है तो इसका मतलब यह भी लगाया जा रहा है कि बजट अच्छा है, क्योंकि आलोचना करना तो उनका विपक्ष धर्म है। जिसका निर्वहन करने के लिए भी यह सरकार पूरे मौके देती है।

इस बारे में एक तरफ सत्ताधारी टीडीपी कहती है कि वाईएसआर कांग्रेस के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी दिल्ली जाकर राज्य की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य के विकास और कल्याण को लेकर वित्तीय सहायता के लिए दो बार दिल्ली गए और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए 15000 करोड़ का विशेष पैकेज लेकर आए। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी इंडिया गठबंधन की राजद सांसद और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी कहती हैं कि राज्य में हत्या और चोरी हो रही है। मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिल रही है। युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही और किसानों की समस्या अभी भी जस की तस बरकरार है। ऐसे में बिहार को 26 हजार करोड़ रुपये आवंटित करना बिहार को झुनझुना देने के बराबर है।

सच कहूं तो पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक केंद्रीय बजट 2024 की आलोचना हो रही है। जहां पंजाब के संसद सदस्यों ने केंद्रीय बजट में धन आवंटन के मामले में उनके राज्य को अनदेखा करने का आरोप लगाया और विरोध प्रदर्शन तक किया। वहीं, महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने भी ताजा बजट में उनके राज्य की उपेक्षा करने का आरोप मढ़ते हुए संसद के बाहर प्रदर्शन तक किया। जबकि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी कहलाने का गौरव प्राप्त है। बजट में महाराष्ट्र को नजरअंदाज करना भाजपा को आगामी विधानसभा चुनाव में भारी पड़ सकती है, क्योंकि यहां की जनता ही असली सबक सिखाएगी।

विपक्ष की इस राय में दम है कि पिछले दस वर्षों से मोदी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि हम सिर्फ नारे सुनते रहते हैं। आज के बजट में भी जुमले ही अधिक रहे। लिहाजा, इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। न तो उन्हें सरकार चलाने आता है और न ही उन्हें लोगों के दर्द से कोई मतलब है।

मौजूदा केंद्रीय बजट पर उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और पश्चिम बंगाल के नेताओं ने जिस तरह से नाखुशी दिखाई है, उस तरह से वैकल्पिक सुझाव नहीं दिए कि इसके बदलते क्या किया जाना चाहिए। यूपी की समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने ठीक ही कहा कि सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। लेकिन टीम मोदी ने जो पिछले 10 वर्षों में बेरोजगारी बढ़ा दी है, उसके दृष्टिगत किये गए कोई ठोस उपाय नजर रही आते।

इस बजट में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी मोटा आवंटन होना चाहिए था, लेकिन बजट में कुछ भी नहीं किया गया है। किचन का ध्यान तक नहीं रखा गया है, क्योंकि सरकार मंहगाई के बारे में कोई कदम नहीं उठाना चाह रही है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने दो टूक कहा कि, अगर मुख्य बातें सामने आ गईं तो सरकार की पोल खुल जाएगी। क्योंकि सरकार गलत है और दिखावा कर रही है। इस बजट में कुछ भी नहीं है और यह केवल गुमराह करने वाला है।

सीधा सवाल है कि उनको मुख्य बातें सामने लाने से रोक कौन रहा है। यदि कुछ होगा, तब तो लाएंगे। उनके लाने का इंतजार रहेगा, ताकि सरकार की पोल पट्टी खुले, यदि कुछ अंदरखाने चल रहा हो तो। मोदी सरकार का पुराना इतिहास बताता है कि ये 2 करोड़ रोज़गार के वादे के साथ सत्ता में आई थी। लेकिन अब 10 साल बीत जाने के बाद चार करोड़ रोजगार पैदा करने की बात करती दिखाई पड़ी, जिसे लोग दोगुना झूठ समझते हैं। उनका तंज है, डबल इंजन की नरेंद्र मोदी की सरकार यानी डबल झूठ। इसका आशय स्पष्ट है कि यह कुर्सी बचाओ बजट है। जब पिछले दस वर्षों में बेरोजगारी दूर नहीं हुई तो अब कोई नई उम्मीद कैसे बांधी जा सकती है। हमलोग इस बारे में सिर्फ नारे सुनते रहे और आज भी बजट के जुमले ही ज्यादा मिले। लिहाजा, इस सरकार से किसी को कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि न तो उन्हें सरकार चलाने आता है और न ही उन्हें लोगों के दु:ख-दर्द से कोई मतलब है। वे बजट बहुत कुछ बोलती हैं, लेकिन किसानों के लिए उन्होंने क्या किया? किसानों के लिए तीन कानून लाए गए, जिसे पूर्णतया वापस लेना चाहिए। इसका स्वरूप बदलकर कभी भी उसपर अमल नहीं किया जाना चाहिए।

इस बजट को जबरदस्त चालाकी भरा बजट भी करार दिया जा सकता है क्योंकि इसमें आम आदमी के सामने आने वाले मुद्दों के बारे में कुछ खास नहीं कहा गया। खासकर मनरेगा का कोई जिक्र नहीं किया गया। वहीं, आम व्यक्ति की आय में सुधार के लिए उठाए गए कदम भी अपर्याप्त हैं। जब बात गंभीर आय असमानता की आती है तो सरकार की ओर से इसे दूर करने वाले प्रयास भी बहुत कम देखने को मिलते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

कुल मिलाकर यह बजट कांग्रेस के घोषणापत्र का कॉपी है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज युवा निधि योजना है। इसके तहत सरकार ने अप्रेंटिसशिप प्राप्त करने वाले प्रत्येक युवा को 5000 रुपये देने की घोषणा की है। इससे यह साबित होता है कि मोदी सरकार राहुल गांधी के विचारों को कॉपी कर रही है। यह खुशी की बात है। हालांकि, इस सरकार ने आंध्र प्रदेश व बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार कर दिया गया और दोनों राज्यों को विशेष पैकेज का लॉलीपॉप थमा दिया।

इसलिए सियासी गलियारे में यह सवाल उठ रहा है कि, क्या निर्मला सीतारमण ने सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बजट पेश किया। या फिर यह महज बैसाखी के सहारे खड़ा रखने वाला बजट है। दरअसल, भाजपा नीत एनडीए सरकार को मालूम है कि अगर बजट बिहार और आंध्र प्रदेश के पक्ष में नहीं होता तो उनकी सरकार गिर जाती। लिहाजा, निर्मला सीतारमण ने भारत नहीं बल्कि एनडीए को फायदा पहुंचाने वाला बजट पेश किया है।

पुराण दिग्दर्शन .... परिचयाध्याय

अष्टादश-संख्या-विज्ञान

गतांक से आगे...

वारह मास, पाँच ऋतुवें, जिस प्रकार एक संवत्सर के अङ्ग हैं इसी तरह एक प्रजापति में सत्रह इष्टिकायें प्रवृद्ध होती हैं। सृष्टि के अष्टादश भेदों पर दृष्टि रखने के लिये सृष्टि प्रतिपादक ग्रन्थ के अष्टादश भेद होना अत्यावश्यक समझा गया है।

(2) वेद में छन्द: से सब सृष्टि मानी गई है। छन्द: यद्यपि गायत्री से लेकर जगती तक सात हैं, किन्तु गायत्री और विराट् वे दो छन्द इस सृष्टि-विद्या में प्रधान माने गये हैं। इन दो में ही समस्त सृष्टि का सार निहित है। वैदिक प्रक्रिया में गायत्री को भूमि-स्थानीया प्रकृति की प्रतिनिधि माना गया है, और विराट् को द्यौ: स्थानीय पुरुष का प्रतिनिधि स्वीकार किया गया है। द्यावाभूमि या विराट्-गायत्री ही सृष्टि के मुख्य आधारभूत तत्त्व हैं। सो गायत्री अष्टाक्षर पाद का छन्द है और विराट् दशाक्षर पाद का। आठ और दश अठारह। यों छन्द:- सृष्टिवाद की ओर दृष्टि आकृष्ट करने के जिये भी सृष्टि-ग्रन्थों का अष्टादश संख्या से सम्बन्ध रचना आवश्यक है। उपर्युक्त विवेचना के आधारभूत नीचे लिखे प्रमाण द्रष्टव्य हैं। यथा:- (4) अनन्त आकाश - जिसमें कि अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड अन्तर्गत है उसे वैदिक परिभाषा में परमाकाश कहते हैं।

एक सूर्य का प्रकाश जितने आकाश में परिव्याप्त रहता है उस ब्रह्माण्ड परिछिन्न आकाश को पुराणाकाश कहते हैं। और अध्यात्म में प्रत्येक प्राणी के हृदयाकाश को दहराकाश कहते हैं। इस आकाश के तीन भेदों में पुराणाकाश का ही पुराण से सम्बन्ध है- यह कहने की आवश्यकता नहीं । पुराणाकाश (ब्रह्माण्डपरिच्छिन्न आकाश) 360 विभागों अंशों में बाँटा जाता है- यह ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता अच्छी तर जानते हैं। इनमें दृश्य आकाश में 180 और अदृश्य आकाश में 180 अंश होते हैं।

क्रमश: ...

संघ के लिए समर्पित संगीतकार सुधीर फडके

साक्षी पांडेय

मराठी सिनेमा में सुधीर फडके को स्वरगंधर्व के नाम से पहचाना जाता है। सुधीर फड़के का जन्म 25 जुलाई 1919 को कोल्हापुर में हुआ। फडके ने कोल्हापुर में वामनराव पाध्ये से शास्त्रीय संगीत में गायन की प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। उनका जन्म का नाम राम फड़के था, लेकिन बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर सुधीर रख लिया। मराठी फिल्म इंडस्ट्री में सुधीर फडके को बाबूजी के नाम से भी जाना जाता है। साल 1941 में एचएमवी के साथ अपना करियर शुरू करने के बाद सुधीर फडके ने साल 1946 में प्रभात फिल्म कंपनी की फिल्म गोकुल से संगीत निर्देशक के रूप में करियर की शुरुआत की। अपने जीवनकाल में उन्होंने 111 फिल्मों में संगीत दिया जिनमें से हिंदी फिल्में भी शामिल है।

कवि जीडी माडगुलकर के छंदों पर आधारित 56 गीतों वाली गीत रामायण सुधीर फडके की सबसे लोकप्रिय कृतियों में से एक है। इन गीतों को सुधीर फडके ने माणिक वर्मा, ललिता देउलकर, लता मंगेशकर, वसंतराव देशपांडे, राम फाटक, उषा अत्रे और खुद की आवाज में रिकॉर्ड किया था। गीत रामायण का पहला प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो पुणे पर 1 अप्रैल 1955 को रामनवमी के दिन किया गया और एक साल तक प्रत्येक रविवार को गीत रामायण का एक नया गीत प्रसारित किया गया। यह उस समय के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रमों में से एक था। गीत रामायण का नौ भाषाओं असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, कोंकणी, सिंधी, तेलुगु और मलयालम अनुवाद हो चुका है।

अपने जीवन के अंतिम दिनों में सुधीर फडके ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर के जीवन पर एक हिंदी फिल्म का भी निर्माण किया। वीर सावरकर का सुधीर फडके के जीवन में काफी प्रभाव रहा है, देशभक्ति के लिए उनसे प्रेरित रहे। गोवा स्वतंत्रता आंदोलन और भारत की स्वतंत्रता के बाद की लड़ाई में भी वह सक्रिय रूप से शामिल थे। वह 60 वर्षों से अधिक समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे। इंडिया हेरिटेज फाउंडेशन के मुख्य प्रेरणास्रोत और संस्थापक सदस्य सुधीर फडके का 29 जुलाई 2002 को ब्रेन हेमरेज की वजह से मुंबई में उनका निधन हो गया। और, उनके पार्थिव शरीर को दादर स्थित वीर सावरकर स्मारक में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था।

सुधीर फडके की बायोपिक का निर्देशन योगेश देशपांडे कर रहे हैं। योगेश देशपांडे कहते हैं, बाबूजी इतने बड़े हस्ती थे कि उनको मैंने संगीतकार और गायक की हैसियत से देखा है। मेरी उनसे पहली मुलाकात पुणे में हुई थी जब वह सावरकर पर फिल्म बना रहे थे। उस समय मेरी उम्र 11-12 साल रही होगी। बाबूजी को बचपन से सुनते आ रहा हूं। किसी पारिवारिक कार्यक्रम में लोग बाबूजी के ही गाने गाते हैं। जब मैंने उनके बारे में जानना शुरू किया, तब जब मुझे पता चला कि 15 वर्ष की उम्र से लेकर 25 वर्ष के उम्र तक का उनका सफर कितना कठिन था। तब गाना गाने के बदले उनको दो रुपये मिलते थे।

प्रतिबंध मुक्त संघ

ललित गर्ग

केंद्र की राजग सरकार ने एक महत्वपूर्ण एवं साहसिक आदेश के जरिये सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर लगी रोक को हटा कर लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक भावना एवं मूल्यों का जीवंत किया है। भले ही इस आदेश को लेकर विपक्षी राजनीतिक दलों की तल्ख प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं संघ ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि तत्कालीन सरकार ने निराधार ही शासकीय कर्मियों के संघ की गतिविधियों में भाग लेने पर रोक लगायी थी। निश्चित ही वर्तमान सरकार का यह निर्णय लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुष्ट करने वाला है क्योंकि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक गैर-राजनीतिक संगठन है, गत 99 वर्षों से सतत राष्ट्र के पुनर्निर्माण एवं समाज की सेवा में संलग्न संघ एक रचनात्मक, सृजनात्मक एवं सांस्कृतिक संगठन है। राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता-अखंडता एवं प्राकृतिक आपदा के समय में संघ के योगदान की विभिन्न राजनीतिक विचारधारा के नेताओं एवं दलों ने प्रशंसा भी की है। इस नये आदेश को लेकर इंडी गठबंधन के दलों में खलबली एवं बौखलाहट का सामने आना स्वाभाविक है, क्योंकि इस आदेश से संघ की ताकत बढ़ेगी, जो इन विपक्षी दलों की चिन्ता का बड़ा कारण है।

दरअसल, आरोप है कि पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने समय-समय पर सरकारी कर्मचारियों की संघ के कार्यक्रमों में शामिल होने पर रोक लगा दी थी। संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर कर्मचारियों को कड़ी सजा देने तक का प्रावधान लागू किया गया था। सेवानिवृत होने के बाद पेंशन लाभ इत्यादि को ध्यान में रखते हुए भी अनेक सरकारी कर्मचारी चाहते हुए भी संघ की गतिविधियों में शामिल होने से बचते थे। हालांकि, इस बीच मध्यप्रदेश सहित कई राज्य

सरकारों ने इस आदेश को निरस्त कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी केंद्र सरकार के स्तर पर यह वैध बना हुआ था। इस मामले में एक वाद इंदौर की अदालत में चल रहा था, जिस पर अदालत ने केंद्र सरकार से सफाई मांगी थी। इसी पर कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार ने नौ जुलाई को एक ऑर्डर जारी करते हुए उक्त प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा कर दी। निश्चित ही यह आदेश संघ से जुड़े एवं राष्ट्रीय विचारधारा वाले सरकारी कर्मचारियों के लिये एक नयी किरण है।

आपातकाल में इंदिरा गांधी सरकार की तानाशाही खुलकर सामने दिखी थी, लेकिन उससे पहले भी तानाशाही कदम उठाए जाते रहे थे। दरअसल, 7 नवंबर 1966 को संसद के सामने गोहत्या के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था। 30 नवंबर 1966 को संघ-जनसंघ के प्रभाव से हिलकर इंदिरा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों के संघ में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया। क्योंकि संघ व जनसंघ के प्रयासों से लाखों लोग जुटे थे और पुलिस के साथ टकराव में कई लोगों की जान गई थी। गोलीबारी में सैंकड़ों निर्दोष साधु-संत मारे गये थे। इस जघन्य हत्याकांड से क्षुब्ध होकर तत्कालीन गृहमंत्री गुलजारी लाल नंदा ने अपना त्यागपत्र दे दिया था। कांग्रेस पार्टी ने 58 साल पहले वर्ष 1966 में संघ पर लगाये गए प्रतिबंध को हटाने के औचित्य पर सवाल उठाए हैं। कहा जा रहा है कि जनसंघ, वाजपेयी सरकार और मोदी सरकार की पिछली एक दशक की सरकार के दौरान भी यह प्रतिबंध नहीं हटाया गया था, फिर अभी हटाने के पीछे गहरी राजनीतिक चाल है। वहीं संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर का कहना है कि संघ पिछले 99 साल से राष्ट्र के सतत निर्माण व समाज सेवा में संलग्न रहा है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते तत्कालीन सरकार ने शासकीय कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक संगठन की गतिविधियों में भाग लेने हेतु निराधार प्रतिबंधित किया था।

क्रांति का फलित है व्यापक स्तर पर होने वाला कोई बड़ा परिवर्तन। व्यक्ति जिस समाज में जीता है, उसकी व्यवस्थाओं, नीतियों और परम्पराओं में जब घुटन का अनुभव करता है जो वह किसी नए मार्ग का अनुसरण करता है। आज आजादी के बाद की राजनीतिक विसंगतियों से पनपी ऐसी ही घुटन से बाहर निकालने के प्रयत्न वर्तमान सरकार द्वारा हो रहे हैं। ऐसा ही एक विशिष्ट उपक्रम है सरकारी कर्मचारियों के संघ की गतिविधियों में भाग लेने पर लगा प्रतिबंध का हटना। इसको लेकर भी विपक्षी दलों द्वारा जनता को गुमराह किया जा रहा है, राष्ट्र की एकता को विखंडित करने के प्रयास हो रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने संघ की गतिविधियों में कर्मचारियों के शामिल होने पर लगे प्रतिबंध को हटाकर नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा की है। नि:संदेह, सरकार का यह निर्णय लोकतंत्र और संविधान की भावना को मजबूत करनेवाला है। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार देता है कि वह विविध सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक संगठनों में शामिल हो सके। एक सामान्य नागरिक की भांति यह अधिकार कर्मचारियों को भी प्राप्त है कि अपने कार्यालयीन समय के बाद सामाजिक गतिविधियों का हिस्सा हो सकते हैं। परंतु, लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देनेवाली कांग्रेस की सरकार ने तानाशाहीपूर्ण तरीके से संघ की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो एक प्रकार से राष्ट्रीय विचार के प्रति झुकाव रखनेवाले लोगों को हतोत्साहित करने का प्रयास ही था। कांग्रेस की नीयत को समझिए कि उसने ऐसा कोई प्रतिबंध इस्लामिक, ईसाई, कम्युनिस्ट और अन्य प्रकार के संगठनों की गतिविधियों में शामिल होने पर नहीं लगाया था। यानी कर्मचारी इस्लामिक एवं ईसाई संगठनों से जुड़ सकता था लेकिन हिन्दू संगठन की गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकता था। कांग्रेस की इस तानाशाही एवं द्वेष का उत्तर संघ ने तो कभी नहीं दिया लेकिन समाज ने अवश्य ही कांग्रेस को आईना दिखाने का कार्य किया।

कांग्रेस लगातार आठ दशकों में हिन्दू-संस्कृति को कमजोर करने की राजनीतिक चालें चलती रही है। जबकि हिन्दू धर्म नहीं, विचार है, संस्कृति है। हिन्दू राष्ट्र होने का अर्थ धर्म से न होकर हिन्दू संस्कृति के सर्वग्राही भाव से है। हिन्दू संस्कृति उदारता का अन्तर्निहित शंखनाद है क्योंकि पूरे विश्व में यह अकेली संस्कृति है जो बहुविचारवाद यानी सभी धर्म, विचार एवं संस्कृतियों को स्वयं में समेटे हैं। हमारे ऋषियों ने हमें यह उपदेश दिया कि 'सत्यं बूर्यात न बूर्यात सत्यं अप्रियं' अर्थात सच बोलो मगर कड़वा सच मत बोलो। हिन्दू संस्कृति की यही महानता और विशेषता रही है कि प्रिय सत्य की वकालत तो करती है मगर इसके कटु होने पर निषेध करने को भी कहती है। यह हिन्दू संस्कृति अहिंसा की संस्कृति है पर जरूरत पड़ने पर शस्त्र उठाकर स्व-रक्षा की बात भी कहती है। हिन्दू शब्द से ही स्वराष्ट्र का बोध होता है जो कि हिन्दू संस्कृति के वृहद स्वरूप का ही सौपान है। लेकिन राजनीतिक कारणों से कांग्रेस एवं अन्य ताकतों ने हिन्दू संस्कृति को निस्तेज करने, संघ को दबाने एवं समाप्त करने के लिए अनेक प्रयत्न किए।

आज का इतिहास

1957 कनाडा में वाटरलू विश्वविद्यालय ओंटारियो शहर में स्थापित किया गया।
1957 फ्रांस से स्वतंत्रता प्राप्त करने के एक साल से अधिक समय बाद, ट्यूनीशिया ने अपने राजशाही, हुसैनिद राजवंश को समाप्त कर दिया, और रिपब्लिक बन गया।
1978 दो प्यूर्टो रिकान स्वतंत्रता-समर्थक कार्यकर्ताओं को विलबा में सेरो मैराविला में उपचुनाव में मार दिया गया था।
1978 लुईस ब्राउन, इन विट्रोफर्टिलाइजेशन के माध्यम से गर्भ धारण करने वाली दुनिया की पहली बच्ची का जन्म इंग्लैंड के ओल्डहैम में हुआ था।
1993 इजरायल की सेना ने लेबनान के खिलाफ एक हफ्ते तक हमला किया और हिजबुल्लाह के लिए दक्षिणी लेबनान का इस्तेमाल करना मुश्किल बना दिया, जिसका आधार इजरायल को समर्थन देना था।
1993 जायोनी शासन के सैनिकों ने दोबारा दक्षिणी लेबनान पर जल थल और वायु आक्रमण किया।
1994 जॉर्डन और इजरायल के बीच 46वर्षों से चल रहा युद्ध समाप्त हुआ।
2000 एयर फ्रांस का कॉनकॉर्ड विमान उड़ान भरने के दो मिनट बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जिसमें 113 लोगों की मौत हुई।
2009 दर्जनों मारे जाते हैं और घायल हो जाते हैं जब वाइल्डफायर फ्रांस, स्पेन, सार्डिनिया और ग्रीस में फैल जाते हैं।
2010 विकीलीक्स ने अफगानिस्तान में युद्ध के बारे में 75,000 वर्गीकृत दस्तावेजों को प्रकाशित किया, जो अमेरिकी सैन्य इतिहास के सबसे बड़े लीक में से एक था।
2011 क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो 2006 में पद छोड़ने के बाद से हवाना के बाहर अपनी पहली उपस्थिति बनाते हैं, जो आर्टिसिसा में एक मकबरे का दौरा करते हैं।
2011 साइकिल चालक अल्बर्टो कोंटाडोर ने 2010 टूर डी फ्रांस जीता, जबकि सात बार के विजेता, लांस आर्मस्ट्रांग ने अपनी अंतिम उपस्थिति दर्ज की।
2012 Ivica Dacic को आधिकारिक तौर पर सर्बिया के प्रधान मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है।
2013 बढ़ती हुई औद्योगिक मंदी के बीच, चीन अपनी आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के प्रयास में व्यापार कर को तोड़ता है और उदारीकरण का निर्यात करता है।

अर्थव्यवस्था को तीव्र गति एवं महाशक्ति बनाने वाला बजट

ललित गर्ग

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का प्रथम सम्पूर्ण बजट वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया, उनकी ओर से प्रस्तुत यह बजट एक मौलिक सोच एवं दृष्टि से दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकते सितारे के रूप में स्थापित करने एवं सुदृढ़ आर्थिक विकास के लिये आगे की राह दिखाने वाला है। संभावना है कि इस बजट में समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, नौकरीपेशा का थोड़ी राहत, बुनियादी ढांचे में निवेश, पर्यटन को बढ़ावा, आदिवासी उन्नयन, क्षमता विस्तार, हरित एवं कृषि विकास, महिलाओं एवं युवाओं की भागीदारी, मोदी के नये भारत-सशक्त भारत-विकसित पर बल दिया गया है। वित्त मंत्री ने सरकार की 9 प्राथमिकताओं -खेती में उत्पादकता और मजबूती बढ़ाना, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट, मानव संसाधन का समावेशी विकास और सामाजिक न्याय, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, अर्बन डेलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्नोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म्स का ऐलान किया है, जो देश को आत्मनिर्भर बनाने की रफ्तार को भी गति देगा। बजट में जहां बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है वहीं महंगाई को नियंत्रित करने की मंशा साफ दिखाई दी है। विकास, स्टार्टअप और रोजगार सृजन के कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह बजट देश को न केवल विकसित देशों में बल्कि इसकी अर्थव्यवस्था को विश्व स्तर पर तीसरे स्थान दिलाने के संकल्प को बल देने में सहायक बनेगा। सातवीं बार बजट प्रस्तुत कर वित्तमंत्री सीमारमण ने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा स्थापित रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जिन्होंने वित्त मंत्री के रूप में पांच वार्षिक बजट और एक अंतरिम बजट पेश किया था।

सशक्त एवं विकसित भारत निर्मित करने, उसे दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाने और अर्थव्यवस्था को तीव्र गति देने की दृष्टि से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को लोकसभा में प्रस्तुत आम बजट इसलिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि मोदी सरकार ने देश के आर्थिक भविष्य को सुधारने पर ध्यान दिया, न कि लोकलुभावन योजनाओं के जरिये प्रशंसा पाने अथवा कोई राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की है। राजनीतिक हितों से ज्यादा देशहित को सामने रखने की यह पहल अनूठी है, प्रेरक है। अमृत काल का विजन तकनीक संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है, जो इस बजट से पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। इस बजट में मध्यम वर्ग को लम्बे अन्तराल के बाद 7 लाख रुपये तक की कुल कमाई करने वालों को बड़ी राहत दी है। नए टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया गया है। साथ ही नए टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में भी कुछ अहम बदलाव करने का एलान किया है। मौजूदा नियमों के तहत एक वित्त वर्ष के दौरान अधिकतम 1 लाख रुपये तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इस लिमिट को बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये सालाना कर दिया

गया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'नवाचार, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिये बुनियादी अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान कोष की स्थापना की घोषणा की। वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का वित्तपोषण पूल भी बनाया जाएगा। मोबाइल फोन और मोबाइल पीसीबीएस तथा मोबाइल चार्जर पर बीसीडी को घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है। वित्तीय घाटा 2024-25 तक सकल घरेलू उत्पाद का 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। लक्ष्य घाटे को 4.5 प्रतिशत से नीचे पहुंचाने का लक्ष्य है। 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों के अनुकूल सड़कें प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 का शुभारंभ किया जाएगा। कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे। छात्रावासों और क्रेच के माध्यम से कार्यबल में महिलाओं की अधिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय सहयोग नीति लाएगी। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी प्रस्ताव है। इस वर्ष शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

भारत की अर्थव्यवस्था को तीव्र गति देने की दृष्टि से यह बजट कारगर साबित होगा, जिसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, रोजगार के नये अवसर सामने आयेंगे, उत्पाद एवं विकास को तीव्र गति मिलेगी। चालू वित्त वर्ष में आर्थिक क्षेत्र में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन इन सब स्थितियों के बावजूद इस बजट प्रावधानों के माध्यम से देश को स्थिरता की तरफ ले जाते दिखाई पड़ रहे हैं। बजट हर वर्ष आता है। अनेक विचारधाराओं वाले वित्तमंत्रियों ने विगत में कई बजट प्रस्तुत किए। पर हर बजट लोगों की मुसीबतें बढ़ाकर ही जाता रहा है। लेकिन इस बार बजट ने अर्थव्यवस्था में नयी परम्परा के साथ राहत की सांसें दी है तो नया भारत- सशक्त भारत-विकसित के निर्माण का संकल्प भी व्यक्त किया है। इस बजट में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, रेलों का विकास, सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचागत क्षेत्रों के विकास के साथ-साथ किसानों, आदिवासियों, गांवों और गरीबों को ज्यादा तवज्जो दी गयी है। सच्चाई यही है कि जब तक जमीनी विकास नहीं होगा, तब तक आर्थिक विकास की गति सुनिश्चित नहीं की जा सकेगी। इस बार के बजट से हर किसी ने काफी उम्मीदें लगा रखी थीं और उन उम्मीदों पर यह बजट खरा उतरा है। विशेषत: नौकरीपेशा लोगों ने राहत की सांस ली है।

संभवत: इस बजट को नया भारत निर्मित करने की दिशा में लोक-कल्याणकारी बजट कह सकते हैं। यह बजट वित्तीय अनुशासन स्थापित करने की दिशाओं को भी उद्घाटित करता है। आम बजट न केवल आम आदमी के सपने को साकार करने, आमजन की आकांक्षाओं को आकार देने और देशवासियों की आशाओं को पूर्ण करने वाला है बल्कि यह देश को समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण एवं दूरगामी सोच से जुड़ा कदम है। बजट के सभी प्रावधानों एवं प्रस्तावों में जहां 'हर हाथ को काम' का संकल्प साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से उजागर हो रहा है। आजादी के अमृत काल में प्रस्तुत यह बजट निश्चित ही अमृत बजट है। जिसमें भारत के आगामी 25 वर्षों के समग्र एवं बहुमुखी विकास को ध्यान में रखा गया है। बीते कुछ सालों में नरेन्द्र मोदी ने इकॉनमी को मजबूत करने के लिए जो नींव रखी थी, अब उस पर मजबूत इमारत खड़ा करने का मौका है।

आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। इससे 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा, जिससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ होगा। बजट में टूरिज्म पर विशेष बल दिया गया है। पर्यटन हमेशा से हमारी सभ्यता का हिस्सा रहा है।. भारत को वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करने के सरकार के प्रयासों से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बिहार में राजगीर और नालंदा के लिए एक व्यापक विकास पहल की जाएगी। सरकार ओडिशा में पर्यटन को बढ़ावा देंगी, जिसमें प्राकृतिक सुंदरता, मंदिर, शिल्पकला, प्राकृतिक परिदृश्य, वन्यजीव अभयारण्य और प्राचीन समुद्र तट हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आशा के अनुरूप ही बजट का फोकस किसानों, आदिवासियों, स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी विकास, रोजगार, युवाओं की अपेक्षाओं, विकास और ग्रामीण क्षेत्र एवं पर्यटन पर रखा है। अपने ढांचे में यह पूरे देश का बजट है, एक आदर्श बजट है। इसका ज्यादा जोर सामाजिक विकास पर है। अक्सर बजट में राजनीति, वोटनीति तथा अपनी व अपनी सरकार की छवि-वृद्धि करने के प्रयास ही अधिक दिखाई देते है लेकिन बावजूद यह बजट राजनीति प्रेरित नहीं, देश प्रेरित है। इस बजट में जो नयी दिशाएं उद्घाटित हुई है और संतुलित विकास, भ्रष्टाचार उन्मूलन, वित्तीय अनुशासन एवं पारदर्शी शासन व्यवस्था का जो संकेत दिया गया है, सरकार को इन क्षेत्रों में अनुकूल नतीजे हासिल करने पर खासी मेहनत करनी होगी।

राजनीति की बदलती करवट को समझे भाजपा

ऋतुपर्ण दवे

उत्तर प्रदेश में किए मंथन के बाद भाजपा की चिंता साफ दिखने लगी है। वहां के उप मुख्यमंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, जिसमें संगठन को सत्ता से बड़ा बताना, कई तरह के संदेश देता है। यह सही है कि भाजपा को 2024 के आम चुनावों में ऐसे नतीजों की उम्मीद हरगिज नहीं थी। लगता नहीं कि अति उत्साह या रणनीतिक विफलता ही थी जो 400 पार का नारा दे दिया और इसे विपक्ष ने लपक कर संविधान से जोड़ दिया और भाजपा उम्मीदों से पीछे रह गई। शायद बयान देते वक्त प्रधानमंत्री ने भी इसके ऐसे दूरगामी परिणामों बारे नहीं सोचा होगा। नतीजों को झुठलाया नहीं जा सकता। रही-सही कसर अभी विभिन्न प्रान्तों से आए विधानसभा के उप-चुनावों ने पूरी कर दी। 13 सीटों में से महज 2 पर ही भाजपा की जीत बताती है कि परिणामों के पीछे भले ही यह कहा जाए कि जहां जिसकी सरकार रही वही जीता लेकिन उत्तराखण्ड और बिहार के नतीजे बताते हैं कि ऐसा नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और 2027 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। साथ ही जिस तरह सोमवार को महाराष्ट्र में राजनीतिक गहमा-गहमी रही और छगन भुजबल ने शरद पवार से दरवाजे पर लंबे इंतजार के बाद मुलाकात की, उसके सियासी मायने बहुत गहरे हैं। क्या लगता है कि इस बार एन.डी.ए. गठबंधन में मोदी सरकार 2014 और 2019 सरीखी मजबूत है? निश्चित रूप से विधानसभा उप-चुनावों के नतीजों से राज्य सरकारों को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता लेकिन नतीजों के पीछे के कारणों, संकेतों और चर्चाओं की अनदेखी भी तो महंगी पड़ सकती है। अभी हुए विधानसभा उप चुनावों के नतीजों को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। इसके पीछे जहां युवाओं में बेरोजगारी की पीड़ा, बार-बार प्रश्न पत्र लीक की घटनाएं, दल-बदल के बाद चुनाव में वही चेहरे और उनकी हार के मायने भी समझने होंगे। भाजपा को सोचना होगा कि जिस पार्टी को अनुशासन का उदाहरण माना जाता था, वहीं से विरोध और चेतावनी के स्वर निकलना कतई साधारण नहीं कहा जा सकता। इस सबके पीछे कहीं न कहीं भाजपा के वे कैडर बेस कार्यकर्त्ता हैं, जो अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से ही पार्टी से जुड़े हैं। वे आज बाहरी लोगों को कतार लगाकर प्रवेश मिलने से कहीं न कहीं उपेक्षित हो रहे हैं। संगठन समर्पित लोगों से चलता है। यदि वही ऐसे लोगों के चलते खुद को पीछे पाएंगे, जो कल तक पार्टी को कोसते थे, तो इसके पीछे के मनोभाव और प्रभाव को कैसे नकारा जा सकता है? जहां हिमाचल में 'ऑप्रेशन लोटस' नाकाम रहा और कांग्रेस पहले की तरह वापस 68 में से 40 सीटों पर दोबारा पहुंच गई, वहीं कमोबेश उत्तराखंड की दो विधानसभा सीटों मंगलौर और बद्रीनाथ में भाजपा को हराना भी इशारा है। मंगलौर सीट पहले बहुजन समाज पार्टी के पास थी, जबकि बद्रीनाथ कांग्रेस के पास। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस विधायक भाजपा में शामिल हुए, जिससे उप चुनाव हुआ। बंगाल में 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ, सभी पर टी.एम.सी. जीती, जबकि पहले 3 सीटों पर भाजपा के विधायक थे। इसी तरह बिहार में हुए एकमात्र उप चुनाव में निर्दलीय का डंका बजना भी मायने रखता है। मध्य प्रदेश में कई चरणों में आगे-पीछे के बाद अंततः भाजपा के जीतने का कारण वहां पर प्रदेश सरकार के तमाम दिग्गजों सहित भाजपा नेताओं की मौजूदगी रही। इससे भाजपा कमलनाथ के किले को दोबारा ध्वस्त करने में कामयाब रही। क्या मतदाताओं ने धर्म की राजनीति को नकार दिया है? राजनीतिक विश्लेषकों के तमाम तर्कों की अनदेखी नहीं की जा सकती, जो मानते हैं कि लोकसभा में अयोध्या और अब उपचुनाव में बद्रीनाथ सीट पर भाजपा की हार के मायने यही हैं।

हरियाणा-दिल्ली में बदलेगा चुनावी परिदृश्य

राज कुमार सिंह

कांग्रेस- 'आप' के अलगाव और इनैलो-बसपा में गठबंधन से आगामी विधानसभा चुनावों में हरियाणा और दिल्ली का राजनीतिक परिदृश्य बदला हुआ नजर आएगा। 18वीं लोकसभा का चुनाव कांग्रेस और 'आप' ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात और गोवा में मिल कर लड़ा था, जबकि पंजाब में दोनों अलग-अलग लड़े। उधर बसपा ने अपने सबसे बड़े प्रभाव क्षेत्र उत्तर प्रदेश में भी अकेले दम चुनाव लड़ा, जिसके चलते उस पर भाजपा की 'बी' टीम होने का आरोप लगा और खाता तक नहीं खुल पाया।

लोकसभा चुनाव में चंडीगढ़ के अलावा कहीं भी नतीजे कांग्रेस और 'आप' की उम्मीदों के मुताबिक नहीं आए। हरियाणा में कांग्रेस ने 'आप' के लिए कुरुक्षेत्र सीट छोड़ी थी तो दिल्ली में 'आप' ने उसके लिए तीन लोकसभा सीटें छोड़ीं। हरियाणा में तो कांग्रेस अपने हिस्से की 9 में से 5 लोकसभा सीटें जीतने में सफल हो गई लेकिन दिल्ली में दोनों ही दलों का खाता तक नहीं खुल पाया और लगातार तीसरी बार भाजपा ने 'क्लीन स्वीप' किया। उसके बाद से ही गठबंधन की व्यावहारिकता पर सवाल उठते रहे। 'आप' के संयोजक अरविंद केजरीवाल के जेल में होने के चलते पार्टी की ओर से तो संकेत ही दिए जाते रहे कि विधानसभा चुनाव अलग-अलग भी लड़ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने स्पष्ट कह दिया कि गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए ही था। हरियाणा में पूर्व मंत्री निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा सरवारा जैसे प्रमुख 'आप' नेताओं को कांग्रेस में शामिल किया गया तो दिल्ली में दोनों दलों के नेताओं-कार्यकर्त्ताओं के बीच की तल्खियां जगजाहिर हैं। केजरीवाल जिस शराब नीति घोटाले में जेल में हैं, उस पर सबसे पहले सवाल उठाते हुए जांच की मांग दिल्ली कांग्रेस ने ही की थी। ऐसे में दोनों ही राज्यों में नेता-कार्यकर्त्ता मिल कर चुनाव नहीं लड़ पाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

जाहिर है, अक्तूबर में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव और फिर अगले साल फरवरी में होने वाले दिल्ली

विधानसभा चुनाव में दोनों दल अलग-अलग लड़ेंगे। संभव है, इस सोच के पीछे पंजाब में लोकसभा चुनाव परिणाम भी रहे हों, जहां कांग्रेस और 'आप' अलग-अलग लड़े तथा अच्छा प्रदर्शन किया। तमाम जोड़-तोड़ के बावजूद भाजपा पंजाब में खाता तक नहीं खोल पाई, लेकिन एक ही फार्मूला हर राज्य पर लागू नहीं हो सकता। पंजाब में 'आप' सत्तारूढ़ है, तो कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल। ऐसे में अलग-अलग लड़ते हुए सत्ता विरोधी मतदाताओं के समक्ष कांग्रेस के रूप में एक विकल्प उपलब्ध रहा। वरना वे शिरोमणि अकाली दल और भाजपा की ओर रुख कर सकते थे, लेकिन हरियाणा और दिल्ली में वैसा नहीं है। हरियाणा में 10 साल से भाजपा की सरकार है। पहले 5 साल इनैलो मुख्य विपक्षी दल था तो पिछले 5 साल से कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। ऐसे में सत्ता विरोधी वोटों के विपक्षी दलों के बीच बंटबारे का सीधा लाभ भाजपा को मिल सकता है। हरियाणा में 'आप' की बड़ी हैसियत नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसे मिलने वाले वोट होंगे तो सत्ता विरोधी ही। वोटों के इसी बिखराव के बीच अपने राजनीतिक पुनरुत्थान की खातिर ओम प्रकाश चौटाला के इनैलो ने मायावती की बसपा से गठबंधन किया है। बसपा भी हरियाणा में बड़ी ताकत कभी नहीं रही, पर खासकर दलित बहुल क्षेत्रों में उसका असर है, जो किसी भी दल के साथ मिल कर चुनावी समीकरण बदल सकता है। 53 सीटों पर लडने वाले इनैलो और 37 सीटों पर लडने वाली बसपा ने बहुमत मिलने पर अभय सिंह चौटाला के मुख्यमंत्री बनने की बात कही है। जाहिर है, वह बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन इस गठबंधन से इन दोनों दलों का पुनरुत्थान संभव है, पर उसका अप्रत्यक्ष लाभ भाजपा को और नुकसान कांग्रेस को होगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि अब 'आप' तथा साढ़े चार साल तक भाजपा के साथ सत्ता में भागीदार रही जजपा क्या चुनावी रणनीति अपनाती हैं। इनैलो की तरह जजपा भी चौधरी देवी लाल के परिजनों की ही पार्टी है। क्या 'आप' और जजपा हाथ मिला कर चुनाव मैदान में उतरेंगी, अगर वैसा हुआ तो 10 साल बाद सत्ता में वापसी की आस देख रही कांग्रेस की मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। देश की राजधानी दिल्ली का राजनीतिक समीकरण एकदम अलग है।

भाजपा के 'क्लीन स्वीप' की 'हैट्रिक' रोकने के मकसद से ही हाल के लोकसभा चुनाव में 'आप' और कांग्रेस ने गठबंधन किया था। 4 सीटों पर 'आप' लड़ी और शेष 3 पर कांग्रेस, पर परिणाम सभी 7 सीटों पर भाजपा की जीत के रूप में सामने आया। इस गठबंधन के चलते दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली समेत कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस छोड़ गए, सो अलग। शायद इसलिए कि पंजाब की तरह दिल्ली की सत्ता भी 'आप' ने कांग्रेस से ही छीनी थी। दरअसल यह कहना ज्यादा सही होगा कि 'आप' का जन्म ही कांग्रेस और वैसी परंपरागत भ्रष्ट राजनीति से मुक्ति के संकल्पों के साथ हुआ था, पर बदलते वक्त ने दोनों को 'इंडिया' गठबंधन में एक ही मंच पर ला दिया। नेताओं ने तो हाथ मिला लिए पर कार्यकर्त्ता और समर्थकों के लिए यह इतना आसान नहीं रहा। अक्सर कहा जाता है कि चुनाव अंकगणित के आधार पर नहीं लड़े जाते, न ही परिणाम उसके अनुरूप निकलते हैं, पर शर्तिया चुनावी जीत का फार्मूला भी आज तक कोई चुनावी पंडित नहीं बता पाया है। ऐसे में राजनीतिक दलों और नेताओं के पास भी एक के असफल हो जाने पर दूसरा दांव आजमाने के सिवाय कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए कांग्रेस और 'आप' के अलगाव तथा इनैलो और बसपा गठबंधन से आगामी विधानसभा चुनाव में दिल्ली और हरियाणा में चुनावी परिदृश्य तो बदल गए लेकिन बदलते समीकरण सत्ता-संघर्ष का संतुलन किसके पक्ष में झुकाएंगे, अभी यह कह पाना बहुत मुश्किल है।

उथल-पुथल से अमेरिकी चौधराहट को चुनौती

राजेश बादल

अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव की दौड़ से जो बाइडेन के अलग होने से भी वहां के आभिजात्य लोकतंत्र पर मंडरा रहे घने काले बादल दूर होने के आसार नहीं हैं। निर्वाचन प्रक्रिया के जरिये राष्ट्रपति चुन लेना एक बात है और मुल्क में दूरगामी शांति, स्थिरता तथा विकास को रफ्तार देना दूसरी बात। दशकों से वैश्विक राजनीति में अमेरिका कुछ-कुछ चौधरी जैसी स्थिति में है। लेकिन अब उसकी यह चौधराहट खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है। बराक ओबामा के बाद अमेरिकी मंच पर जो नायक अवतरित हुए, उन्होंने अपनी नीतियों से पद की गरिमा और मर्यादा को बाजार में उछाल दिया है। संसार इन दिनों जिन हालात का सामना कर रहा है, उसमें अमेरिका ने सिर्फ अपनी चिंताओं को प्राथमिकता दी है। यह अमेरिका की उस छवि से भिन्न है, जो दुनिया भर में छोटे और विकासशील देशों को भी पालता-पोसता था।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बिखरने के बाद तीसरी दुनिया के देशों का स्वर मद्धम पड़ा है. कुछ समय तक तो वैश्विक चौधरी उनकी देखभाल का अभिनय करता दिखाई दिया, बाद में शनै: शनै: उसने खुद को समेट लिया. अब वह एक अधिनायक की भूमिका में है। अन्य देशों से यह अधिनायक अपेक्षा करता है कि वे अमेरिकी स्वार्थों की रक्षा करें। लेकिन उन देशों का हित संरक्षण करने के लिए वह तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प ने इस एकतरफा अपेक्षाओं पर सर्वाधिक जोर दिया था। ट्रम्प ने अपने कार्यकाल में इतने शातिर झूठ बोले थे कि शेष विश्व ने उन पर भरोसा करना ही छोड़ दिया था। अमेरिका के एक बड़े अखबार ने तो ट्रम्प के झूठे कथनों पर एक परिशिष्ट ही प्रकाशित कर दिया था। अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में वे इतने अलोकप्रिय हो गए थे कि उनके मुकाबले जो बाइडेन को जीतने के लिए एड़ी-चोटी का जोर नहीं लगाना पड़ा। गौरतलब यह है कि बाइडेन भी कम झूठे नहीं हैं। उनके झूठ के चुटकुले प्रचलित हैं। अब जो बाइडेन अपने कामकाज

से अमेरिकी अवाम को नाराज कर बैठे हैं। उनके खाते में उपलब्धियां ही नहीं हैं। इसलिए अमेरिका का भद्रलोक डोनाल्ड ट्रम्प पर ही भरोसा करता दिखाई देने लगा है। पर, जो बाइडेन के स्थान पर कमला हैरिस की उम्मीदवारी से मामला रोचक और रोमांचक हो सकता है।

दरअसल कमला हैरिस के लिए भी राष्ट्रपति पद बहुत दूर की कौड़ी है। उपराष्ट्रपति रहते हुए उनके अपने खाते में याद रखने लायक कुछ खास नहीं है। अगर पिछले चुनाव पर नजर डालें तो जो बाइडेन और कमला हैरिस की जोड़ी से अमेरिका के आम मतदाता ने बड़ी उम्मीदें लगाई थीं। मगर इस जोड़ी ने निराश किया। कमला और बाइडेन के मतभेद सार्वजनिक हो गए और कमला ने अपने को अलग-थलग कर लिया। वे अश्वेतों का भला नहीं कर पाईं, जबकि उनके नाम पर अश्वेतों ने वोट किया था। इसी बीच मुल्क की समस्याएं दिनोंदिन विकराल होती गईं, विदेश नीति ढुलमुल रही और अमेरिका सरपंच की भूमिका से अपने को उतार बैठा। यहां तक कि यूरोपीय राष्ट्रों से भी उसके संबंधों में वह गरमाहट नहीं रही।

भारत के संदर्भ में डोनाल्ड ट्रम्प और जो बाइडेन की तुलना की जाए तो दोनों एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं। ट्रम्प ने ईरान से भारत के बेहतर रिश्तों में खटास डालने का काम किया। ईरान पर प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए लेकिन उसका घाटा भारत को हुआ। इंदिरा गांधी ने जिस चाबहार बंदरगाह की नींव डाली थी,उससे भारत को मिलने वाला लाभ सिकुड़ गया। भारत को अपना तेल आयात भी कम करना पड़ गया। जब अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान से बाहर निकालना था तो ट्रम्प ने पाकिस्तान को भरोसे में लिया और भारत का अरबों का पूंजी निवेश बेकार गया। जब-तब भारत के खिलाफ ट्रम्प के बड़बोले बयान भी घनघोर आपत्तिजनक थे। एक बार तो उन्होंने कहा था कि भारत जितना अफगानिस्तान में खर्च कर रहा है, उतना तो अमेरिका का सिर्फ एक दिन का खर्च है। अफगानिस्तान में भारत की ओर से पुस्तकालय बनाने की भी उन्होंने खिल्ली उड़ाई थी. एच1-बी वीजा निलंबित करने के उनके फैसले से भारतीय बहुत नाराज रहे थे।

इसी तरह जो बाइडेन का कार्यकाल रहा। जो बाइडेन और कमला हैरिस दोनों ही भारत की कश्मीर नीति के आलोचक थे। इसलिए उन्होंने चुनाव जीतने के बाद भी भारत से दूरी बनाए रखी। रूस-यूक्रेन जंग में वे भारत से अपेक्षा करते रहे कि भारत रूस से तेल आयात बंद कर दे और यूरोपीय देशों की तरह पिछलग्गू बना रहे। भारत की भौगोलिक और सामरिक प्राथमिकताओं को वे समझने को तैयार नहीं थे। चीन और पाकिस्तान से शत्रुतापूर्ण संबंधों के बाद वे चाहते थे कि रूस से भी भारत के रिश्ते बिगड़ जाएं। अमेरिका के उप सुरक्षा सलाहकार और एक फौजी कमांडर हिंदुस्तान आकर धमकाने वाली भाषा बोल कर जाते हैं। उसके बाद भारत में उसके राजदूत ने भारत को चेतावनी दे डाली थी।

भारत कैसे भूले कि 1965 और 1971 की जंग में अमेरिका ने पाकिस्तान का ही साथ दिया था और रूस ने भारत के साथ भरोसे वाली दोस्ती निभाई थी। जब चीन के साथ भारत की डोकलाम में खूनी भिड़ंत हुई तो अमेरिका ने तीन दिन तक चुप्पी ओढ़ रखी थी। बीते दिनों मैंने इसी पन्ने पर लिखा था कि रूस-चीन तो जंग लड़ चुके हैं, पर भारत और रूस के रिश्ते इतने गहरे हैं कि उन पर कोई खतरा नहीं है। लब्बोलुआब यह कि अमेरिका का जो भी नया नियंता बने, उसे अपनी अधिनायकवादी सोच पर संयम रखना होगा और लोकतांत्रिक सिद्धांतों का साथ देना होगा। ट्रम्प पर कितना भरोसा मतदाता करेंगे - कहना मुश्किल है। दूसरी तरफ कमला हैरिस की राह भी आसान नहीं है। वे अश्वेतों के साथ भेदभाव नहीं रोक पाई हैं।

यूपी विधानसभा में अखिलेश का नेता प्रतिपक्ष चुनने का सियासी समीकरण

अजय कुमार

उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और समाजवादी पार्टी (सपा) के सामने सबसे बड़ी चुनौती नेता प्रतिपक्ष के चयन की है। 2022 से अखिलेश यादव इस पद की जिम्मेदारी निभा रहे थे, लेकिन अब कन्नौज से सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस बीच, यह देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव अपनी जगह पर किसे नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं। सपा में इस समय दो अलग-अलग धड़े हैं। एक धड़ा शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाने की कोशिश में है, जबकि दूसरा धड़ा उनके विरोध में है। शिवपाल यादव, जो सपा के संस्थापक सदस्य हैं और पूर्व में छह बार विधायक रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष के पद

के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार माने जा रहे हैं। हालांकि, उनके खिलाफ भी कुछ तर्क प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव के कई करीबी नेता शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष के पद पर न नियुक्त करने के पक्ष में हैं। उनका कहना है कि शिवपाल यादव अच्छा वक्ता नहीं हैं और सदन में पार्टी की बात को ठीक से नहीं रख पाएंगे। इसके अलावा, यह भी कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाना सपा पर यादव परस्ती का आरोप लगवा सकता है, जो कि हाल के लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सपा के अध्यक्ष से लेकर लोकसभा के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पद पर यादव समुदाय के सदस्य होने से विपक्ष को घेरने का मौका मिल सकता है। इसलिए, यह संभावना है कि अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी किसी गैर-यादव नेता को सौंप सकते हैं। शिवपाल यादव को मुख्य सचेतक का पद देने का विचार किया जा सकता है। इस समय, विधानसभा में एक मजबूत नेता की तलाश की जा रही है जो अखिलेश यादव की जगह ले सके और योगी सरकार को चुनौती दे सके। अंबेडकर नगर से विधायक राम अचल राजभर और कौशांबी से विधायक इंद्रजीत सरोज के नाम इस फेहरिस्त में शामिल हैं। राम अचल राजभर गैर-यादव ओबीसी समुदाय से आते हैं, जबकि इंद्रजीत सरोज दलित समुदाय के पासी जाति से हैं। पासी समुदाय ने 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा को समर्थन दिया है और पांच पासी सांसद चुने गए हैं। इस स्थिति में, इंद्रजीत सरोज के नेता प्रतिपक्ष बनने की संभावना अधिक दिखाई देती है। इंद्रजीत सरोज सदन में उपनेता के पद पर हैं और पार्टी के सियासी समीकरण में फिट बैठते हैं। सपा की रणनीति में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक (पीडीए) समुदायों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ऐसे में, राम अचल राजभर या इंद्रजीत सरोज को उचित नेतृत्व की भूमिका देना पार्टी के पीडीए फॉर्मूले के अनुरूप हो सकता है। यह सपा के भविष्य की सियासत और संगठनात्मक रणनीति के अनुरूप हो सकता है। आखिरकार, नेता प्रतिपक्ष के चयन का निर्णय सपा नेतृत्व पर निर्भर करेगा। पार्टी के भीतर विभाजन और विभिन्न तर्कों के बीच, यह देखना होगा कि अखिलेश यादव कौन सा रास्ता अपनाते हैं और पार्टी को सशक्त बनाने के लिए कौन सा कदम उठाते हैं।

एकाग्रता से बढ़ाएं कार्यकुशलता

काम करते वक्त ध्यान का भटकना लगभग सभी के साथ होता है, किंतु अगर यह बहुत ज्यादा होने लगे तो इससे कार्य पर तो असर पड़ता ही है, व्यक्ति का स्वभाव भी प्रभावित होने लगता है।

जिनमें एकाग्रता की कमी होती है वे बहुत चिंचित, उदास, चिड़चिड़े और सहमे से रहते हैं। कुछ अपराध भावना व हीनभावना के शिकार भी हो जाते हैं। आत्मविश्वास की कमी, असुरक्षा की भावना, कुंठा, गुस्सा, चिड़चिड़ापन व घबराहट बढ़ जाती है। ध्यान भटकने की समस्या में आमतौर पर आत्म नियंत्रण व व्यवहार नियंत्रण का अभाव होता है। ध्यान भटकने से अक्सर गलतियां होने की संभावना रहती है। जिनका ध्यान जल्दी बंट जाता है, उनकी मनोदशा में भी जल्दी-जल्दी उतार-चढ़ाव आते रहते हैं।

एकाग्रता बढ़ाने के लिए निम्न बातों पर गौर फरमाएं -

- एकाग्रता बढ़ाने के लिए मेडीटेशन और योग करें। इससे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का विकास होता है।
- एकाग्रता बढ़ाने के लिए किसी केंद्र बिंदु पर जितनी देर हो सके, ध्यान केंद्रित करें। धीरे-धीरे ध्यान केंद्रित करने का समय बढ़ाएं।
- माता-पिता को चाहिए कि शुरू से ही बच्चों को ध्यान केंद्रित करने की शिक्षा दें।
- अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से और समय पर करें, इससे काम का अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ेगा और किसी तरह की चिंता भी नहीं रहेगी।
- उद्देश्यों में कामयाब न होने पर भी नकारात्मक विचार आने लगते हैं और नकारात्मक विचार मन में हीनभावना लाते हैं अतः ऐसी भावना से बचें।
- सफलता प्राप्त होने पर स्वयं को सकारात्मक सोच से भरें, जिससे काम करने का उत्साह बना रहे।
- बचपन से ही बच्चों की ताकतों और कमजोरियों को पहचानने की कोशिश करें। जहां तक हो सके घर का माहौल हंसी-खुशी का बनाकर रखें, ताकि बच्चों में नकारात्मक सोच पैदा न हो।
- अपने कार्य को समय-समय पर रिव्यू करते रहें।
- बच्चों की बातों को अनसुना करने की बजाए गौर से सुनें और उन पर ध्यान दें।
- एकाग्रता से काम करने के लिए शांतिपूर्ण माहौल का होना जरूरी है। इसलिए काम करते समय रेडियो या टीवी न चलाएं।
- काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए खुद को अनुदेश देते रहें कि आपका ध्यान केवल अपने निर्धारित काम के अलावा और कहीं नहीं जाए।
- यदि काम करते समय ध्यान टीवी देखने या किसी मनोरंजन के साधन की ओर जाए तो पहले उसे पूरा करें, फिर काम करें। इससे ध्यान भटकेगा नहीं और आपको संतुष्टि भी मिलेगी।
- विद्यार्थियों को चाहिए कि पढ़ाई के दौरान बीच-बीच में ब्रेक लें। ब्रेक के समय पढ़ाई की चिंता छोड़कर हल्का-फुल्का कुछ खा-पी लें। घरवालों के साथ बातें और हंसी मजाक करते रहें। ऐसा करने से मूड बदलेगा और फिर से पढ़ाई करने में अधिक ध्यान लगेगा।

ये हैं सफलता के मंत्र

पढ़ाई में टॉपर बनना आपका सपना है तो इस सपने को आप मेहनत से हकीकत में बदल सकते हैं। इन सक्सेस मंत्रों को अपनाकर प्रतियोगी परीक्षा और एक्जाम में सफल हो सकते हैं।

कड़ी मेहनत- सफलता हासिल करने का पहला मंत्र है कड़ी मेहनत। मेहनत का कोई शॉर्टकर्ट नहीं होता। यदि अपने पाठ्?यक्रम की आवश्यकता के अनुसार कड़ी मेहनत करते हैं तो उसका फायदा मिलता ही है।

खुश रहें- किसी भी परीक्षा की तैयारी के दौरान नकारात्मक विचारों से दूर रखें। हमेशा पॉजीटिव थिकिंग रखें। हमेशा खुश रहने की कोशिश करें।

फोकस बनाए रखें- बिना फोकस बनाकर कई घंटे पढ़ाई करने से अच्छा है कि कुछ घंटे ध्यान लगाकर पढ़ाई करें। कुछ देर ही सही पर मन को एकाग्र रखकर पढ़ाई करें।

सपनों को सच करने के लिए संघर्ष करें- हमेशा जीवन में बड़े सपने देखें और लागं टर्म गोल बनाएं। जब भी ऐसा लगे कि आप हार रहे हैं तो अपने सपनों को याद करें। खुद को यह अहसास दिलाएं कि सफने इतने कीमती हैं कि ऐसा संघर्ष उन सपनों के सामने कुछ भी नहीं है।

ऐसे मिलती है सफलता

अक्सर देखा जाता है कि युवा जब अपना सफल करियर नहीं बना पाते हैं तो इसका दोष वे दूसरों को देते हैं। अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने लगते हैं। यह याद रखिए अपनी नाकामी के जिम्मेदार आप खुद हैं।

वे अनेक बातों का रोना रहते हैं, जैसे हमारे माता-पिता के कम पढ़े-लिखे होने के कारण वे हमारा करियर में मागदर्शन नहीं कर सके। हम पढ़ने की सुविधाएं नहीं मिली। पढ़ाई के दौरान हमें घर के कामों में लगाए रखा। घर में ज्यादा सदस्य होने से घरवालों ने हमारी ओर ध्यान नहीं दिया।

ये ऐसी कुछ बातें हैं जो असफल युवा कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर व्यक्ति कुछ करना चाहे और उसके हौसले बुलंद हों तो उसकी राह में कितनी भी मुसीबतें आएं वह सफल हो जाता है।

एक अंग्रेजी कहावत का हिन्दी अर्थ है- किसी एक विचार या लक्ष्य के प्रति समर्पण के कारण ही एक सामान्य योग्यता रखने वाला व्यक्ति असाधारण प्रतिभा से संपन्न व्यक्ति बनता है।

कठिनाइयां हर किसी के जीवन में आती हैं बस उनका स्वरूप और उनसे लड़ने के तरीके अलग हो सकते हैं। उन कठिनाइयों को ढाल बनाकर अपनी नाकामी को उजागर न करें, बल्कि हर स्थिति से निकलना सीखें।

याद रखिए दुनिया भी उन्हीं को याद रखती है जो संघर्षों से निकलकर सफलता के शिखर पर पहुंचता है। नाकामियों को रोना छोड़कर चल पड़िए मंजिल की राह पर। मुश्किलें तो आएंगी। अपनी नाकामियों को सफलता की मंजिल पाने का पड़ाव मानिए।

हिटलर का प्रसिद्ध वाक्य है, जो बिना संघर्ष के जीतता है वह विजेता कहलाता है लेकिन जो संघर्षों का सामना करके जीतता है वह इतिहास बनाने वाला कहलाता है।

इन बातों जीवन में हमेशा रखें ध्यान-

- अगर आप किसी क्षेत्र में करियर बनाने में असफल हो गए हैं तो यह न सोचिए कि सिर्फ वही क्षेत्र आपके लिए बना था।
- आप दूसरे क्षेत्र में प्रयास कर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं।
- पहाड़ी की चढ़ाई करते समय हमेशा ऊपर चढ़ने वालों को देखना चाहिए। नीचे वालों को देखेंगे तो हमें ऊंचाई से डर लगेगा।
- अपने आपको मोटिवेट कीजिए। सफलता की जो अनुभूति रहती है उसका मजा ही कुछ और है।
- जीत कुछ कर गुज़रने में है, हारकर बैठने में नहीं। प्रयास से सफलता मिल ही जाती है।

फोटोग्राफी में रखें इन बातों का ध्यान

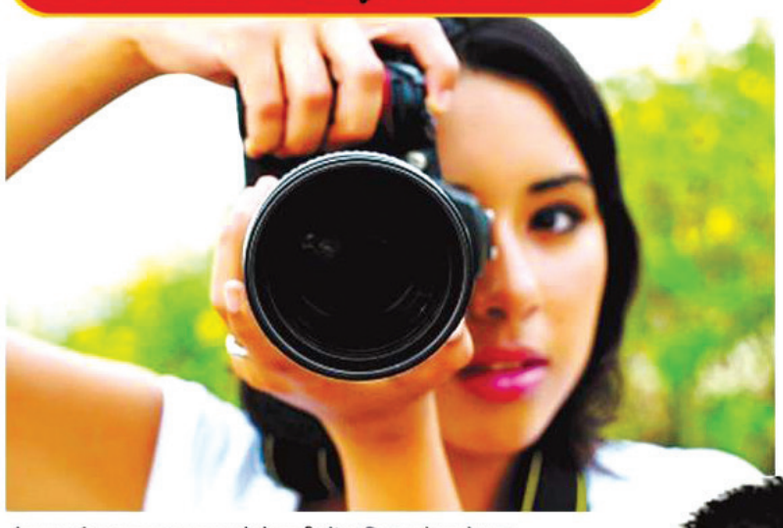

फैशन और वाइल्ट लाइफ फोटोग्राफी में रुचि रखने वाले युवा इसे अपना पेशन मानते हैं। इस फील्ड में क्रिएटीविटी, टेक्निक, ट्रेनिंग, हार्डवर्क, ग्लैमर, एडवेंचर सबकुछ है। सही ट्रेनिंग और गाइडेंस से इस फील्ड में करियर बनाने का स्कोप बढ़ गया है। कई डिग्री होल्डर फोटोग्राफर्स भी फैशन और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की बारीकियां सीख रहे हैं।

करियर संभावनाएं- फैशन इंडस्ट्रीज, कार्पोरेट और इंडस्ट्रीयल सेक्टर के विकसित होने से इस फील्ड में संभावनाएं बढ़ गई हैं। फैशन इंडस्ट्री के फलने-फूलने के साथ ही फैशन फोटोग्राफी में ग्लैमर जुड़ चुका है। आज हर कंपनी अपने प्रोडक्ट के साथ कैलेंडर, मैगजीन, विज्ञापन ब्रोशर प्रकाशित करती है। इनमें आकर्षक और स्टाइलिश फोटो की खास भूमिका होती है। इन सबके लिए फैशन फोटोग्राफर की बहुत जरूरत है। तकनीकी रूप से सक्षम होने पर इस क्षेत्र में भविष्य बहुत उज्जवल है।

शैक्षणिक योग्यता- फोटोग्राफी के लिए कम से कम ग्रेजुएशन होना जरूरी है। देशभर में कई इंस्टीट्?यू फोटोग्राफी में डिग्री या सर्टिफिकेट कोर्स करवाते हैं। एक सक्सेसफुल फोटोग्राफर बनने के लिए डीप स्टडी और अच्छे विजन का होना जरूरी है। अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, औरंगाबाद जैसे शहरों में संस्थानों द्वारा फोटोग्राफी का विधिवत प्रशिक्षण दिया जाता है। इन संस्थानों में दो-तीन वर्षों के डिग्री कोर्स एवं ट्रेनिंग दी जाती है।

इन बातों का रखें ध्यान-

- फोटोग्राफर बनने के लिए किताबी कम और प्रेक्टिकल नॉलेज ज्यादा जरूरी है।
- अपने फील्ड की पूरी जानकारी, लेटेस्ट ट्रेंड पर नजर और आने वाले ट्रेंड की खबर होना जरूरी।
- फोटोग्राफी का बेसिक नॉलेज के लिए किसी प्रतिष्ठित इंस्टीट्?यूट से ट्रेनिंग लें।
- ट्रेनिंग के बाद सबसे ज्यादा जरूरी है विजन।
- इस फील्ड में बहुत ज्यादा पेशन रखने की जरूरत है। यह फील्ड पेशन, कॉन्फिडेंस और हार्ड वर्क मांगता है।
- फोटोग्राफी में सक्सेस धीरे-धीरे ही मिलती है।

फोटोग्राफी के टॉप इंस्टीट्यूट

- नेशनल इंस्टीट्?यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद।
- सर जेजे स्कूल ऑफ एप्लाइड आर्ट, मुंबई।
- जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद।

कैसे सामना करें इंटरव्यू का

इंटरव्यू का नाम आते ही दिल में एक डर पैदा होने लगता है। इंटरव्यू के लिए आपको हर तरह से तैयार रहना पड़ता है। इंटरव्यू से पहले कई अनजाने सवाल सताने लगते हैं।

कहते हैं कि वेल बिग्निंग इज हाफ डन अगर आपने इंटरव्यू में शुरू से ही अपना विश्वास बनाए रखा और इंटरव्यू पेनल के शुरुआती सवालों का प्रभावशाली अंदाज में जवाब दे दिया तो मान लें कि आपकी सफलता की संभावनाएं प्रबल हैं।

इटरव्यू में जाने से पहले नीचे दिए गए टिप्स पर गौर करें। ये टिप्स आपके लिए बड़े मददगार साबित होंगे। टिप्स पढ़ने के बाद आप पाएंगे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ गया है।

1. कहा जाता है कि पहला इंप्रेशन ही आखिरी इंप्रेशन होता है। इसलिए मेंटल लेवल पर तैयारी के साथ-साथ आप यह न भूल जाएं कि इंटरव्यू में आपकी बौद्धिक क्षमता के अलावा आपकी बॉडी लेंग्वेज को भी परखा जाएगा। वेल ड्रेस्ड होकर ही इंटरव्यू में जाएं क्योंकि इससे आप आत्मविश्वास से भर जाएंगे।
2. अपने साथ जरूरी कागजात जरूर ले जाएं। मसलन अपने सर्टिफिकेट, एकेडमिक एचीवमेंट और बायोडाटा जो आपने इंटरव्यू से पहले भेजा था, उसकी एक प्रति अवश्य ले जाएं।
3. अपने कागजात इंटरव्यू में तभी प्रस्तुत करें, जब आप से मांगें जाएं।
4. इंटरव्यू में लेट न हों। कम से कम पंद्रह मिनट पहले पहुंचने की कोशिश करें।
5. यदि किसी कारण न चाहते हुए भी इंटरव्यू में लेट हो जाएं तो उसके लिए सबसे पहले क्षमा मांगें और देर से आने के कारण का उल्लेख करें।
6. इंटरव्यू कक्ष में पहुंचते ही इंटरव्यू पैनल के सदस्यों का अभिवादन जरूर करें।
7. इंटरव्यू पैनल के हर सवाल को ध्यान से सुनें और यदि किसी सवाल को सुनने में कोई शक हो तो निम्रतापूर्वक उसे दोहराने के लिए कहें।
8. सवालों के जवाब विश्वास के साथ और संक्षेप में दें जब तक कि विस्तृत जानकारी देने के लिए न कहा जाए।
9. जिस संस्थान में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उसके बारे में मोटी जानकारी पहले ही जुटा लें।
10. जब आपसे पूछा जाए कि इस पद के लिए आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है तो इसका जवाब चतुराई से दें। सीधे ही कोई फिगर बताने से बेहतर होगा कि आप कहें कि एस पर द मार्केट स्टेंडर्ड। इंटरव्यू पैनल के दोबारा पूछने पर आप अपने मुताबिक कोई फिगर बता सकते हैं।
11. इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यू पैनल से आई कॉन्टेक्ट कायम रखें।
12. अगर किसी विषय में जानकारी नहीं है तो उसे स्वीकार कर लें।
13. कभी झूठ न बोलें। अगर इंटरव्यू पैनल ने आपका झूठ पकड़ लिया तो आपकी सारी इंप्रेशन खराब हो जाएगी।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

नीट मामला: भाजपा ने राहुल पर भ्रम फैलाने का लगाया आरोप

नईदिल्ली। भाजपा ने बुधवार को राहुल गांधी पर कुछ स्थानों पर नीट-यूजी पेपर लीक के बाद भारत की परीक्षा प्रणाली में विश्वास की कमी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और पूछा कि क्या वह इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माफी मांगेंगे। अदालत ने मंगलवार को परीक्षा को रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग करने वाली याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि इसकी पवित्रता के प्रणालीगत उल्लंघन के कारण इसे विकृत किया गया था। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लगभग 23.5 लाख बच्चों ने नीट 2024 की परीक्षा में हिस्सा लिया था। ये परीक्षा 571 शहरों में 4,750 केंद्रों पर हुई थी। खुद सरकार ने सीबीआई इंक्वायरी दी थी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अब दोबारा परीक्षा कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इसके कारण बहुत समस्या उत्पन्न होगी, बच्चों का सेशन गड़बड़ होगा।

जंतर मंतर पर धरने पर बैठे जगन मोहन रेड्डी

नईदिल्ली। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी दिल्ली के जंतर मंतर पर आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव का भी उन्हें साथ मिला। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने अपने बयान में कहा कि आज वे सत्ता में हैं, कल हम सत्ता में आ सकते हैं। कल हम सत्ता में थे, लेकिन हमने कभी इस तरह के व्यवहार का प्रचार नहीं किया था। उन्होंने कहा कि हमने कभी भी हमलों और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने को प्रोत्साहित नहीं किया है। आज आंध्र प्रदेश में स्थिति अलग है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हम दिल्ली में इस देश के सामने खड़े हैं और हम सवाल करते हैं कि क्या आंध्र प्रदेश में लोकतंत्र प्रचलित है या नहीं, जहां लोकतंत्र शब्द का अर्थ समान न्याय है और आज राज्य में न्यायसंगत न्याय से इनकार किया गया है और लोकतंत्र लंगड़ा कर खड़ा है।

राजद विधायक रेखा देवी पर विधानसभा में भड़के नीतीश

पटना। बिहार विधानसभा मॉनसून सत्र चल रहा है। 5 दिनों तक चलने वाले बिहार विधान सभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को जमकर हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष के नेता पर भड़क गए। नीतीश ने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता जातिगत जनगणना है। विपक्ष के विधायकों ने सदन के अंदर और बाहर जमकर हंगामा किया। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव भड़क गए। सीएम नीतीश राजद की विधायक रेखा देवी पर भड़क गए। आप लोग सुनना नहीं चाहते हैं। 2005 से महिला को बढ़ाया है। सीएम नीतीश राजद की विधायक रेखा देवी पर कहा कि आप लोग हाय-हाय कर रहे हो। महिला हो कुछ आता है। विधानसभा में महिला विधायक पर हत्थे से नीतीश कुमार उखड़ गए। कहा कि महिला हो, कुछ जानती हो, चुप रहो। 2005 से पहले कुछ बोलने को मिलता था? विपक्षी सदस्य वेल में पहुंच गए और बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग करते हुए जोरदार हंगामा मचाया।

ये बजट युवाओं और महिलाओं को लाभ देगा : वीरेंद्र सचदेवा

नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा ने केंद्रीय बजट 2024-25 का स्वागत किया है, इसे पीएम नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत के दृष्टिकोण के भारत को विकसित करने का माध्यम बताया है। सचदेवा ने कहा है कि अगले एक दशक या उससे अधिक समय तक भारत को सभी के लिए घर के एजेंडे पर काम करना होगा और जाहिर तौर पर इसे ध्यान में रखते हुए आवास योजना के लिए बजटीय प्रावधानों में वृद्धि की गई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बजट 2024-25 में आवास योजना निवेश में वृद्धि से दिल्ली के गरीबों को लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि केजरीवाल सरकार दिल्ली में केंद्रीय आवास योजनाओं को लागू करने की अनुमति नहीं दे रही है। इसके अलावा, यह बजट महिलाओं और युवाओं के लिए लाभकारी है क्योंकि यह सीधे तौर पर छोटे शहरों के नए नियुक्त युवाओं, जो द्वितीयक और तृतीयक नौकरियों को अपना रहे हैं, को आयकर राहत प्रदान करता है।

आतिशी केजरीवाल के जेल और बेल क्लब में शामिल हुई

नईदिल्ली। दिल्ली भाजपा मीडिया प्रमुख एवं प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने अप्रैल में दिल्ली सरकार की मंत्री श्रीमती आतिशी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था और लंबी बहस के बाद अदालत ने मुकदमे को स्वीकार कर लिया और जून में सुश्री आतिशी को समन किया जब उन्होंने ऑनलाइन उपस्थित होकर नई तारीख के लिए स्थगन मांगा और अदालत ने 23 जुलाई 2024 के लिए स्थगन की अनुमति दी। वह अपने वकील के साथ अदालत में उपस्थित हुईं और जमानत मांगी क्योंकि मानहानि का अपराध जमानती है जमानत मिल गई। दिल्ली भाजपा मीडिया प्रमुख ने कहा है कि दिल्ली सरकार की मंत्री सुश्री आतिशी के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर और राउस एवेन्यू कोर्ट से जमानत लेने के साथ, हम कानूनी लड़ाई का पहला दौर जीत चुके हैं और मामले को मुकदमे के चरण में ले आए हैं। जमानत लेने के बाद, सुश्री आतिशी अरविंद केजरीवाल के जेल और बेल क्लब में शामिल हो गई हैं।

बजट को लेकर संसद में विपक्ष ने किया विरोध-प्रदर्शन

■ **खड़गे बोले- हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं**

नईदिल्ली। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट में विपक्षी शासित राज्यों के खिलाफ भेदभाव के खिलाफ बुधवार को संसद के अंदर और बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि कई लोगों को (केंद्रीय बजट में) न्याय नहीं मिला। हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस सांसद अमरिन्दर सिंह राजा वारिंग ने आरोप लगाया कि हम आज पंजाब को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश और बिहार को सब कुछ आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब को बाढ़ सहायता भी नहीं दी गई। पंजाब ने बीजेपी को एक भी सीट नहीं दी और यही कारण है कि राज्य की अनदेखी की गई है।

आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने दावा किया कि कुछ राज्यों के साथ पूर्ण भेदभाव किया गया है। बिहार और आंध्र प्रदेश को इतनी सारी परियोजनाएं आवंटित की गई हैं। उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में, सरकार को समर्थन देने वाले कुछ राज्यों को बढ़ावा देना संविधान की भावना के विरुद्ध है। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश को कुछ देने की बात तो छोड़िए, (बजट में) इसका नाम तक नहीं लिया गया... सरकार बचाने के लिए वे कुछ को धन दे रहे हैं और दूसरों को नजरअंदाज कर रहे हैं।

शिवसेना (यूबीटी) सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि यह बजट लाडला बिहार, लाडला आंध्र प्रदेश और लाडला ओडिशा के लिए है। आंध्र प्रदेश ने विशेष पैकेज मांगा था लेकिन राज्य को 15,000 करोड़ रुपये देकर उनका मुंह बंद कर दिया गया। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि उन्होंने अपने गठबंधन को बचाने के लिए बजट में सभी राज्यों को छोड़ दिया है और केवल दो राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया है। अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक लाभ देने वाली योजनाएं और सुधार उनके बजट से गायब थे।

आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि केंद्रीय बजट में राजस्थान का जिक्र तक नहीं...बजट के बाद युवाओं और किसानों को निराशा हाथ लगी. बजट में किसानों की आय दोगुनी करने की बात नहीं की गई. हम उन राज्यों का विरोध नहीं कर रहे हैं जिन्हें विशेष पैकेज मिला है, लेकिन राजस्थान को भी विशेष पैकेज मिलना चाहिए था। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि बजट से पूरा देश परेशान है. सभी राज्यों के लोग परेशान हैं क्योंकि भाजपा उनके बुनियादी मुद्दों को हल करने में विफल रही है। इस बजट में सरकार की मजबूरी साफ नजर आ रही है. इंडिया ब्लॉक बजट में हुए अन्याय का विरोध कर रहा है।

बजट में भेदभाव के आरोप पर वित्त मंत्री ने विपक्ष को दिया जवाब

नईदिल्ली। विपक्ष के भेदभावपूर्ण केंद्रीय बजट के विरोध के जवाब में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में सरकार के रुख का बचाव किया और बजटीय निर्णयों के पीछे के तर्क को स्पष्ट किया। अपने भाषण के दौरान, सीतारमण ने इस बात पर जोर दिया कि हर बजट घोषणा में हर राज्य का उल्लेख करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि हर बजट में, आपको इस देश के हर राज्य का नाम लेने का मौका नहीं मिलता। कैबिनेट ने वडावन पर एक बंदरगाह स्थापित करने का निर्णय लिया था। लेकिन कल बजट में महाराष्ट्र का नाम नहीं लिया गया। क्या इसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र खुद को उपेक्षित महसूस करता है?

वित्त मंत्री ने कहा कि यदि भाषण में किसी विशेष राज्य का नाम लिया गया है, तो क्या इसका मतलब यह है कि भारत सरकार के कार्यक्रम इन राज्यों में नहीं जाते हैं? यह कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष का लोगों को यह आभास देने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है कि हमारे राज्यों को कुछ भी नहीं दिया गया है। यह एक अपमानजनक आरोप है। %भेदभावपूर्ण% बजट पर विपक्ष के राज्यसभा से वॉकआउट करने से पहले, विपक्ष के नेता राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये कुर्सी बचाने के लिए ये सब हुआ है... हम इसकी निंदा करेंगे और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के दल विरोध करेंगे। अगर संतुलन नहीं होगा तो विकास कैसे होगा?

राज्यसभा में आज एक नाटकीय घटनाक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जैसे ही केंद्रीय बजट पर अपना भाषण देने के लिए उठीं, विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। वित्त मंत्री ने सदन को संबोधित करना शुरू ही किया था कि विपक्षी सांसद एकजुट होकर अपनी सीटें खाली छोड़कर सदन से बाहर चले गए।

एमएसपी की गारंटी के लिए सरकार पर डालेंगे दबाव: राहुल

■ **संसद में किसान नेताओं से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने की मुलाकात**

नईदिल्ली। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को संसद भवन में किसान नेताओं से मुलाकात की। 12 सदस्यीय किसान नेताओं का प्रतिनिधिमंडल संसद भवन में गांधी के कार्यालय पहुंचा था। कथित तौर पर किसान नेताओं ने अपनी लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने के लिए एक निजी विधेयक पेश करने का भी अनुरोध किया। इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के नेताओं ने देश भर में मोदी सरकार के पुतले जलाने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) गारंटी को वैध बनाने के लिए एक नया विरोध प्रदर्शन शुरू करने की अपनी योजना की घोषणा की थी।

इस विरोध प्रदर्शन में विपक्ष के निजी विधेयकों के समर्थन में एक लंबा मार्च शामिल होगा। किसान नेताओं से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हमने अपने घोषणापत्र में कानूनी गारंटी के साथ एमएसपी का जिक्र किया है। हमने आकलन कर लिया है और इसे लागू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अभी हमारी एक बैठक हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि हम इंडिया गठबंधन के दूसरे नेता से बात करेंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे कि देश के किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारी किसान 15 अगस्त को देश भर में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, जब देश स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। वे नए आपराधिक कानूनों की प्रतियां भी जलाएंगे। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) के नेताओं ने यह भी कहा कि किसानों का दिल्ली चलो मार्च 31 अगस्त को 200 दिन पूरे कर लेगा और लोगों से पंजाब और हरियाणा सीमा पर खनौरी, शंभू आदि में पहुंचने की अपील की। घोषणा के बाद, उन्होंने दोनों संगठनों को सूचित किया कि संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) 1 सितंबर को उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक मेगा रैली करेंगे।

राज्यसभा से विपक्ष के वॉकआउट पर बिफरे सभापति धनखड़

ये पार्टियों के आत्म-मंथन करने का समय

नई दिल्ली। बजट के विरोध में विपक्ष ने आज राज्यसभा से वॉकआउट किया। इस पर राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। सभापति ने कहा अगर ऐसा चलता रहा तो इससे लोकतंत्र गंभीर खतरे में पड़ जाएगा। सभापति ने ये भी कहा कि राजनीतिक पार्टियों के लिए अब आत्म मंथन का समय आ गया है।

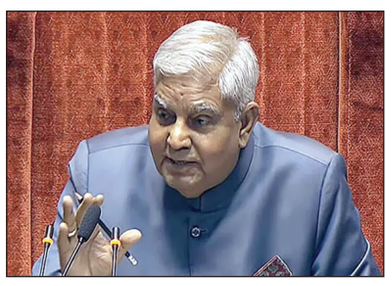

सभापति ने कहा कि बजट पर आज चर्चा सूचीबद्ध थी और मुझे उम्मीद थी कि नियमों का पालन होगा और माननीय सदस्य बजट पर चर्चा करेंगे, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि रणनीति के तहत ये किया गया। मैं सदस्यों से अपील करता हूं कि अगर इसी तरह से सदन में हंगामा होता रहा और इसे राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया तो इससे लोकतंत्र गंभीर खतरे में पड़ जाएगा

खेल
प्रमुख समाचार

श्रीलंका को टी20 मैच से पहले लगा तगड़ा झटका!

कोलंबो। श्रीलंका को भारत के खिलाफ पहले टी20 मैच से पहले बड़ा झटका लगा है, क्योंकि श्रीलंका को अपने अनुभवी तेज गेंदबाज दुष्मंथा चमीरा की सेवाएं नहीं मिलेंगी। चमीरा चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए हैं।

जुलाई 2024 से शुरू होने वाली तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज के पहले टी20 मैच से कुछ दिन पहले श्रीलंका को बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज दुष्मंथा चमीरा लंका प्रीमियर लीग 2024 के दौरान लगी चोट के कारण टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। यह खबर श्रीलंका द्वारा टी20 सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम की घोषणा के एक दिन बाद आई है।

श्रीलंका क्रिकेट चयन समिति के अध्यक्ष उपुल थरंगा के अनुसार, चोट की गंभीरता का खुलासा नहीं किया, लेकिन पुष्टि की कि 32 वर्षीय तेज गेंदबाज सीरीज में हिस्सा नहीं लेंगे। चमीरा भारत के खिलाफ फॉर्मेट में श्रीलंका के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।

असिथा फर्नांडो ने 15 मैचों में 26.68 की औसत से 16 विकेट लिए हैं। पहले टी20 मैच से पहले असिथा फर्नांडो उनकी जगह टीम में शामिल हो सकते हैं। चमीरा के बाहर होने के बाद, श्रीलंका ने ऑलराउंडर दासुन शनाका को छोड़कर मथीशा पथिराना और नुवान तुषारा के रूप में दो विशेषज्ञ तेज गेंदबाजों को अपनी टीम में शामिल किया है।

श्रीलंका की अपडेटेड टी20 टीम

चैरिथ असलांका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसल परेरा, अविष्का फर्नांडो, कुसल मेंडिस, दिनेश चांडीमल, कामिंडु मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, डुनिथ वेललागे, महीश थीक्षाना, चामिंडु विक्रमसिंघे, मथीशा पथिराना, नुवान तुषारा।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 280 अंक लुढ़का निफ्टी भी लाल निशान में

नईदिल्ली। बजट 2024 के पेश होने के बाद आज दूसरे दिन भी शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। आज शेयर बाजार लाल निशान में ही ओपन हुए थे और लाल निशान में ही बंद हुए। सेंसेक्स 280.16 अंकों की गिरावट के साथ 80,148.88 के लेवल पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी-50 65.55 अंकों की गिरावट के बाद 24,450 के लेवल से नीचे आकर 24,413.50 पर बंद हुआ। शेयर बाजार में आज लगातार चौथे दिन गिरावट देखने को मिली। बजट आने से दो दिन पहले यानी 19 जुलाई से लगातार शेयर बाजार में गिरावट जाती है। माना जा रहा था कि सरकार कैपिटल गेन टैक्स को लेकर कोई बड़ा फैसला बजट में ले सकती है। और बजट के दिन ऐसा ही देखने को मिला। शेयर बिक्री से मिले मुनाफे पर टैक्स बढ़ाने की वजह से बाजार का सेंटिमेंट आज भी डाउन रहा।

प्रॉपर्टी की बिक्री पर इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा

नईदिल्ली। इनकम टैक्स डिपार्मेंट ने बुधवार को कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के रेट दर में कटौती से ज्यादातर टैक्स पेयर्स को 'पर्याप्त कर बचत' होने की उम्मीद है। बता दें कि बजट में लॉन्ग टर्म तक रखी गई हाउसिंग प्रॉपर्टी की बिक्री से कमाए गए कैपिटल गेन पर टैक्स की दरें कम कर दी गई हैं, लेकिन टैक्स पेयर्स को मिलने वाला 'इंडेक्सेशन' बेनिफिट हटा दिया गया है। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एलटीसीजी को 'इंडेक्सेशन' बेनिफिट समेत 20 प्रतिशत से घटाकर बिना 'इंडेक्सेशन' के 12.5 प्रतिशत कर दिया गया है। इंडेक्सेशन बेनिफिट हटने का मतलब है कि जब आप अपने कोई भी प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो आप अपने कैपिटल गेन टैक्स को एडजस्ट करने के लिए महंगाई का दावा नहीं कर सकेंगे।

एमएंडएम का जून तिमाही का शुद्ध लाभ 45 प्रतिशत बढ़ा

नईदिल्ली। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज का चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में शुद्ध लाभ 45 प्रतिशत बढ़कर 513 करोड़ रुपये हो गया है। गैर-बैंकिंग कंपनी का शुद्ध लाभ बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 353 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी की शुद्ध ब्याज आय जून तिमाही में 15 प्रतिशत बढ़कर 1,932 करोड़ रुपये हो गई तथा ब्याज मार्जिन पिछली तिमाही की समान अवधि के 7.1 प्रतिशत से घटकर 6.6 प्रतिशत रह गया। समीक्षाधीन तिमाही के दौरान इसकी कुल आय 20 प्रतिशत बढ़कर 3,760 करोड़ रुपये हो गई तथा प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तियां (एयूएम) 23 प्रतिशत बढ़कर 1.06 लाख करोड़ रुपये हो गईं। कंपनी की ऋण लागत एक साल पहले की समान तिमाही के 526 करोड़ रुपये से घटकर 448 करोड़ रुपये रह गई, जिससे लाभ वृद्धि में मदद मिली।

बजाज ग्रुप की पहली तिमाही में मुनाफा 10 फीसदी बढ़ा

नईदिल्ली। बजाज ग्रुप की फाइनेंशियल कंपनी बजाज फिनसर्व ने आज वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही के परिणाम जारी कर दिए हैं। एक्सचेंजों को दी गई जानकारी में कंपनी ने बताया कि जून तिमाही में उसका नेट मुनाफा 10 फीसदी बढ़कर 2,137.70 करोड़ रुपये हो गया। जबकि, एक साल पहले की समान अवधि में बजाज फिनसर्व का नेट मुनाफा 1,942.63 करोड़ रुपये रहा था। बजाज फिनसर्व लिमिटेड ने शेयर बाजार को बताया कि जून तिमाही में कंपनी की कुल आय 35.22 फीसदी बढ़कर 31,480.14 करोड़ रुपये हो गई, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह 23,280 करोड़ रुपये रही थी। फाइनेंशियल कंपनी ने बताया कि इस तिमाही के दौरान उसका कुल खर्च 25,514.14 करोड़ रुपये हो गया है। एक साल पहले की समान अवधि में यह 18,157.41 करोड़ रुपये था।

लोकलुभावनवाद नहीं, समावेशी नीतियों पर ध्यान संतुलित और सधा हुआ बजट

डॉ. अश्विनी

तेईस जुलाई, 2024 को पेश किये गये बजट की खासियत यह है कि यह मोदी सरकार की प्राथमिकताओं पर केंद्रित है। निर्मला सीतारमण ने बहुत स्पष्ट रूप से सरकार की नौ प्राथमिकताएं बतायी हैं, जैसे कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार और कौशल, समावेशी मानव संसाधन, विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार, अनुसंधान और विकास तथा अगली पीढ़ी के सुधार।

प्रधानमंत्री मोदी से पूर्व, हम अभी तक केंद्र सरकार के बजट देखते थे, जो लोकलुभावनवाद से प्रेरित थे, क्योंकि वे अगले चुनाव में वोटों पर नजर गड़ाये हुए थे। लेकिन मोदी सरकार पहले भी लोकलुभावनवादी के रूप में देखे जाने से बचती रही है और इसके बजाय विकास और समावेशी नीतियों पर ध्यान केंद्रित करती रही है। इस तरह, यह बजट भी उसी राह पर है।

हम समझते हैं कि रोजगार दो स्रोतों से आता है। पहला, नौकरी और दूसरा स्वरोजगार। स्वरोजगार का लाभ यह है कि स्वरोजगार करने वाले लोग नौकरी के सृजनकर्ता भी होते हैं। इस संदर्भ में बजट में दो बड़ी घोषणाएं हैं। एक, बिना गारंटी वाले मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ा कर 20 लाख करने से संबंधित है। स्टार्ट-अप को भी एंजल टैक्स के माध्यम से कुछ राहत दी गयी है। दूसरी योजना रोजगार के संबंध में है और वह भी संगठित क्षेत्र में। इसके लिए तीन योजनाएं शुरू की गयी हैं। एक प्रमुख योजना अप्रेंटिसशिप योजना है, जिसके तहत एक अप्रेंटिस को 5000 रुपये दिये जायेंगे। इस योजना के वित्तपोषण के लिए कॉरपोरेट सीएसआर फंड का उपयोग कर सकते हैं।

यह योजना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे एक तरफ बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा, तो दूसरी तरफ व्यवसायों के लिए कुशल कर्मचारियों की कमी भी दूर होगी। यदि यह योजना सफल होती है, तो इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। छोटे उद्योगों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। फिलहाल सरकार ने केवल बड़े उद्योगों को ही इस योजना में शामिल किया है और इसका कारण यह है कि सीएसआर के माध्यम से जो पैसा आता है, वह इसमें इस्तेमाल हो पायेगा। इसके अलावा कंपनियों को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से पहली नौकरी का पहला वेतन सरकार द्वारा देने का वादा भी इस बजट में किया गया है। नियोक्ता को इपीएफओ में प्रोविडेंट फंड जमा करने हेतु सहयोग भी दिया जायेगा।

बजट के बारे में सामान्य तौर पर माना जाता है कि यह सरकार की नीतियों का आईना होता है। बीते 10 वर्षों में सरकार जिन नीतियों पर चली है, उस कारण अर्थव्यवस्था को गति मिली है। चाहे वह संवृद्धि की बात हो या, महंगाई पर रोक लगाने की, सरकार सफल रही है। क्योंकि पिछली सरकार के 10 वर्षों की औसत महंगाई की दर 8.6 प्रतिशत थी, जो इस सरकार के समय लगभग छह प्रतिशत है। इन बातों से उत्साहित होकर सरकार ने इस बार के बजट में कई ऐसे प्रावधान किये हैं जो विकसित राष्ट्र बनने की प्रक्रिया के लिए जरूरी हैं।

क्योंकि बार-बार कहा गया है कि 2047 तक हमें विकसित राष्ट्र बनना है। किसानों की बात करें, तो किसान क्रेडिट कार्ड, सब्जी उत्पादन एवं आपूर्ति शृंखला के लिए एफपीओ का गठन और डेयरी क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन समेत तमाम उपाय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बजट में दिखाई देते हैं। जहां तक गरीबों की बात है तो आवास उपलब्ध कराने को लेकर सरकार ने पहले ही घोषणा की थी कि ग्रामीण क्षेत्र में वह तीन करोड़ और शहरी क्षेत्र में एक करोड़ आवास मुहैया करायेगी, यह अच्छा कदम है। आप कल्पना कीजिए कि जो कच्चे घर में रह रहा है, यदि उसे पक्का घर मिल जाए, तो निश्चित तौर उसके जीवन स्तर में बदलाव आयेगा। जीवन स्तर में बदलाव से उस व्यक्ति के कार्य क्षमता में भी वृद्धि होगी, जो बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। संभवत: इन्हीं सब कारणों से बीते वर्षों में भारत की बहुआयामी गरीबी में काफी कमी आयी है।

कांग्रेस का जंगी विधानसभा घेराव

बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस का सरकार पर बड़ा हमला
पुलिस के वाटरकेनन, लाठीचार्ज से अनेकों कार्यकर्ता घायल

रायपुर/24 जुलाई 2024। बिगड़ती कानून व्यवस्था और साय सरकार की नाकामी को लेकर कांग्रेस ने पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में सरकार पर बड़ा हमला बोला। हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मंडी चौक पर एकत्रित होकर विधानसभा की ओर बढ़े, जिन्हें पुलिस ने बलपूर्वक रोकने का प्रयास किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज स्वयं बेरिकेट पर चढ़कर पुलिस के द्वारा लगाये गये अवरोध को तोड़कर आगे बढ़े। प्रदेश भर से राजधानी रायपुर पहुंच रहे कांग्रेसजनों को पुलिस ने रास्ते में रोका, भिलाई, बिलासपुर, बलौदाबाजार, धमतरी, महासमुंद की ओर से आने वाले कांग्रेसजन कार्यक्रम स्थल नहीं पहुंच पाये। इसके लिये भाजपा सरकार ने पुलिस को आगे कर के तमाम अवरोध पैदा किया। लोगों की गाड़ियों को बीच रास्ते में रोका। हजारों लोग मीलो पैदल चलकर कार्यक्रम में शामिल हुये 25000 से अधिक लोग घेराव कार्यक्रम में शामिल हुये। कांग्रेस के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस ने वाटरकेनन, लाठीचार्ज भी किया, जिसमें अनेकों कार्यकर्ता घायल हो गये। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का कपड़ा भी पुलिस ने फाड़ दिया।

घेराव कार्यक्रम के पहले सभा को संबोधित करते हुये एआईसीसी के महासचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को धन्यवाद देते हुये कहा आपके आव्हान पर एवं समूचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यहां पर एकत्रित होना इस विधानसभा के बाहर प्रदेश के लोगो की पीडा और उनके जख्म को जगजाहिर करते हुये न्याय की मांग करने के लिये और सरकार की नींद खोलने के लिये सभी कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता की होती है और संख्या बल की होती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीवित है, ताकतवर है और जवाबदेही तय करने के लिये तैयार है। छत्तीसगढ़ में पांच साल कांग्रेस की सरकार रही है और जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने कानून और नियम बनाये उनको खत्म करके भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने जनता के साथ अन्याय करने का काम किया। पिछले 7 महीने में जो हत्या, बलात्कार, लूटपाट, चोरी, डकैती हुई है और जो गोलियां चली है उसकी जवाबदेही तय करने को सरकार को मजबूर करने का समय आ चुका है। एक राजनैतिक कार्यकर्ता होने के नाते हमें याद रखना होगा हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है। ये 139 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी है, अहिंसा और विन्रमता और मजबूती से अपनी बात रखनी होगी। 2018 के बाद भूपेश बघेल प्रदेश अध्यक्ष थे और मैं राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष था, वैसी ही आक्रमकता से हमें लड़ना है। सरकार जो घमंड में है जो कांग्रेस के लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे करती है। बलौदाबाजार के प्रकरण में सतनामी समाज के खिलाफ साजिश पूर्ण कार्यवाही करके लोगों में बंटवारा करना चाहती है। कोई भी समाज हो विशेष रूप से सतनामी समाज उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचेगा। कांग्रेस के लोगो को जेल में बंद करोगे और अपनी नाकामी छुपाने के लिये कांग्रेस के लोगो के ऊपर मुकदमे करोगे, आम जन को परेशान करोगे उसका विरोध होगा। वहां पर बाहर के कौन लोग आये थे सरकार जवाब दे, सूचना तंत्र पूरी सरकार कहा सो रहा था? ये सरकार रायपुर से नहीं चलती, ये सरकार दिल्ली से चलती है। यहां के मुख्यमंत्री और मंत्री को पता नहीं हो क्या रहा है? यहां पर वो जो लिखकर दिल्ली से भेज देते है उस काम को भाजपा सरकार करती है। आज समय है कांग्रेस पार्टी को एकजुटता से आगे बढ़ने का, आज पूरी जनता उमीद करती है कांग्रेस पार्टी पूरी आवाज को उठायेगी। कांग्रेस के बड़ी संख्या में और भारी बारिश के बावजूद और सरकार चारो तरफ पुलिस ने बैरीगेट्स लगाकर रोकने का काम किया। उसके बावजूद हजारों की संख्या में लोग आये। गरीब, किसान और नौजवान का आवाज उठाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। राहुल गांधी देश की संसद में किसानों की आवाज को उठाया है और हमेशा कहते है डरना नहीं है ये लोग चिल्लाते है, डराते है और पुलिस प्रशासन का डर दिखाते है। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है और चार साल का समय है भाजपा सरकार को नींद खोलकर काम करना है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सभा को संबोधित करते हुये कहा कि कांग्रेस की लड़ाई भाजपा सरकार के लापरवाही के खिलाफ है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बदहाल है। हमारी लड़ाई जनता के हित और सुरक्षा के लिये है। हम विधानसभा के बाहर सड़कों पर लड़ने के लिये तैयार है।

देश में कैंसर रोकथाम की दिशा में तेजी से हो रहा काम

रायपुर सांसद अग्रवाल के सवाल पर पीएमओ ने दिया जवाब

रायपुर। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार कैंसर के रोकथाम की दिशा में तेजी से काम कर रही है। देश में सभी उच्च मूल्य की कैंसर रोधी दवाओं के दामों में समूह समझौता के परिणामस्वरूप औसतन 82% फीसदी की कमी आई है। यह कहना है रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल का।

दरअसल बृजमोहन अग्रवाल ने देश में उच्च गुणवत्ता वाली कैंसर केयर को लेकर लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ जानकारी मांगी थी कि, जिसमे पूछा गया था कि, रोगियों को वहनीय लागत पर उच्च गुणवत्ता वाली कैंसर-परिचयर्या सुनिश्चित करने, पिछले चार वर्षों के दौरान कैंसर-केयर के क्षेत्र में आरम्भ किए गए विशिष्ट अनुसंधान के परिणाम और राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड की कैंसर-केयर में भूमिका, इसके केंद्रों, अनुसंधान संस्थानों आदि की राज्य-वार सूची मांगी थी।

जिसपर राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि, परमाणु ऊर्जा विभाग के तत्वावधान में एक सहायता प्राप्त संस्थान टाटा स्मारक केंद्र 60ः40 अनुपात मॉडल पर काम करते हुए किफायती लागत पर उच्च गुणवत्ता की कैंसर देखभाल प्रदान कर रहा है। जिसके तहत 60त्न रोगी अत्यधिक आर्थिक सहायता पर इलाज या लगभग निःशुल्क इलाज प्राप्त कर रहे हैं और 40 फीसदी काफी रियायती दरों पर इलाज करा रहे हैं।

साथ ही कैंसर प्रबंधन के लिए स्रोत आधारित दिशानिर्देशों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ा गया है जिससे लाभार्थियों के लिए देखभाल सुविधा की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। जितेंद्र सिंह ने पिछले चार वर्षों में कैंसर देखभाल के क्षेत्र में टीएमसी द्वारा शुरू किए गए विशिष्ट अनुसंधान परिणाम का विवरण भी प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि, अब तक 400 से अधिक ऑन्कोलॉजिस्ट प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। टीएमसी द्वारा किए गए एक प्रमुख यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण (आरसीटी) से इलाज की दरों में 26त्न की वृद्धि हुई। जिससे प्रतिवर्ष 1 लाख लोगों की जान बचाने की आशा है। बृजमोहन अग्रवाल के सवालों का जवाब देते हुए सिंह ने बताया कि, राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड अब 340 कैंसर केंद्रों, अनुसंधान संस्थानों, रोगी पक्षपोषण समूहों, परोपकारी संगठनों और व्यावसायिक संस्थाओं के एक बड़ा नेटवर्क में विकसित हो गया है।

जो एनसीजी प्रतिवर्ष 8.5 लाख से ज्यादा नए रोगियों का उपचार करता है, जो भारत के कुल कैंसर रोगियों का लगभग 60 प्रतिशत है। भारत में कैंसर देखभाल के सभी हितधारकों को शामिल करते हुए, यह कैंसर की रोकथाम में एक मजबूत, एकीकृत और शक्तिशाली साधन है।

राज्य मंत्री तोखन साहू ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से की मुलाक़ा

रतनपुर के महामाया मंदिर को 'प्रसाद' योजना में शामिल करने की मांग

रायपुर। भारत में कई सिद्ध मंदिर हैं, जिनमें इन 51 शक्तिपीठों का विशेष धार्मिक महत्व रहा है. इन शक्तिपीठों में बिलासपुर जिले के रतनपुर में स्थित महामाया मंदिर भी है. छत्तीसगढ़ के आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के समक्ष महामाया मंदिर रतनपुर को 'प्रसाद' योजना में शामिल करने और उन्नयन के लिए विशेष कॉरिडोर बनाने की मांग की है. बता दें किवर्तमान में रतनपुर एक छोटा नगर है, जो मंदिरों और तालाबों के लिए विख्यात है. यह जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है. यहां स्थित प्राचीन महामाया मंदिर का निर्माण राजा रत्नदेव प्रथम द्वारा ग्यारहवीं शताब्दी में कराया गया था. ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से यह देश और प्रदेश के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है. यहां हर वर्ष लगभग 15 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं. वर्तमान बिलासपुर सांसद और आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने जनहित में महामाया मंदिर की महत्ता और छत्तीसगढ़ राज्य के करोड़ों लोगों की आस्था का सम्मान करते हुए भारत सरकार की तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान (प्रसाद) योजना के तहत इस मंदिर के विकास के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की. इस योजना के तहत महामाया मंदिर का विकास होने से देश-विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का सृजन होगा. राज्य मंत्री तोखन साहू ने इस विषय में पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से सार्थक प्रयास करने का आश्वासन प्राप्त किया. बिलासपुर सांसद और आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने बिलासपुर की जनता की ओर से उनका आभार व्यक्त किया.

प्रमुख समाचार छत्तीसगढ़/राजधानी

कांग्रेस शासन में छत्तीसगढ़ बन गया था अपराध गढ़

रायपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कानून-व्यवस्था और अपराध को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन को मुद्दाविहीन कांग्रेस का राजनीतिक प्रदर्शन बताया है। देव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सशक्त नेतृत्व में भाजपा की प्रदेश सरकार में सबको न्याय मिलने की गारंटी है और सबको न्याय मिल रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष देव ने कहा कि सभी की मुकम्मल सुरक्षा का समुचित उपाय प्रदेश सरकार ने किया है, जबकि कांग्रेस के कार्यकाल में अपराधी बेलगाम थे और अपराधियों को संरक्षण देने का काम होता था। कांग्रेस के राज में जो पीड़ित होते थे, उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई थी। कांग्रेस शासनकाल में अंजाम दिए गए ऐसे तमाम अपराधों पर अब भाजपा सरकार कार्रवाई कर रही है और अपराधियों को सींखचों के पीछे डाल रही है। देव ने कहा कि इससे अधिक शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि कांग्रेस के शासन में कांग्रेस के ही विधायक तक तत्कालीन गृह मंत्री के सामने यह बोलते थे कि पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है और सब्जी वालों, टमाटर वालों से भी पैसे वसूली करती है। देव ने कहा कि आज कानून-व्यवस्था के नाम पर प्रलाप करते कांग्रेसी पहले यह बताएं भूपेश सरकार के समय आखिर हो क्या रहा था?

लोस में रायपुर सांसद बृजमोहन ने रेलवे से जुड़े मुद्दे उठाए

रायपुर। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान रेलवे से जुड़े मुद्दे उठाए। उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से रेल मंत्रालय की 100 प्रतिशत विद्युतीकरण की पहल की राज्य-वार स्थिति पर सवाल पूछा था। जिसपर रेल मंत्री ने लिखित में उत्तर दिया है कि, छत्तीसगढ़ समेत 20 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में बड़ी लाइन नेटवर्क का 100 फीसदी विद्युतीकरण कर लिया गया है। बृजमोहन अग्रवाल ने सवाल भारतीय रेल में पर्यावरण अनुकूल इंधन और ऊर्जा के नए स्रोतों का विस्तार करने में भारतीय रेलवे वैकल्पिक ईंधन संगठन (आईआरओएएफ) द्वारा की गई प्रगति की जानकारी मांगी थी। जिसपर रेल मंत्री ने बताया कि, भारतीय रेल में आईजारओएएफ की स्थापना वैकल्पिक ईंधन की खोज के लिए की गई थी। इससे कर्षण के लिए मिश्रित बायो-डीजल का उपयोग करने तथा डीजल के स्थान पर आंशिक रूप से सीएनजी और एलएनजी के उपयोग को प्रोत्साहन मिला है। कर्षण के लिए डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (डेमू) रेक पर हाइड्रोजन ईंधन सेल के रेट्रो-फिटमेंट के लिए एक प्रायोगिक परियोजना भी शुरू की गई है।

आम बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला है: अभिषेक

रायपुर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को संसद में पेश किए गए बजट को भाजपा युवा नेता अभिषेक टंडन ने सामूहिक रूप से सुना और बजट भाषण के बाद खुशियां मनाई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। अभिषेक टंडन ने बजट की सराहना करते हुए इसे विकसित भारत के सपने को साकार करने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट नए कीर्तिमान स्थापित करेगा और युवाओं, महिलाओं, गरीबों और किसानों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। टंडन ने कहा कि छत्तीसगढ़ के बजट में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हर वर्ग और जिले को अनेकों सौगातें दी हैं। उन्होंने विपक्ष द्वारा आलोचना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि देश की जनता मोदी के विजन को देख रही है और उन्हें समर्थन दे रही है। अभिषेक टंडन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री को बधाई देते हुए कहा कि इस बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। यह बजट युवाओं को रोजगार देने, कौशल को बढ़ावा देने और महिला सशक्तिकरण का है।

महादेव सट्टा एप से जुड़े गिरोह का भंडाफोड़ = बाप-बेटे समेत चार आरोपी गिरफ्तार, कई खातों में करोड़ों का लेन-देन, सवा तीन करोड़ रुपए **जशपुर.** छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में महादेव सट्टा एप से जुड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है. पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सट?टा एप के 03 करोड़ 24 लाख 77 हजार रुपए को फ्रीज कराया जा रहा है. आरोपियों से नगदी रकम 2 लाख तीस हजार रुपए, विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक, बैंक का सील, सिमकार्ड एवं पासपोर्ट आदि जब्त किया गया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने संदिग्ध बैंक खातों में करीब 28 करोड़ 76 लाख रुपए जमा एवं 25 करोड़ 51 लाख रुपए आहरण किया है. बाप-बेटा एवं अन्य मिलकर क्षेत्र के भोले-भाले ग्रामीणों का खाता खुलवाकर 95 बैंक खातों के कुल 124 एटीएम कार्ड से करोड़ों रुपए की हेरा-फेरी की है. ये आरोपी महादेव सट्टा एप से जुड़े लोगों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दे रहे थे. आरोपियों के विरूद्ध थाना तपकरा में मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही. **ये हैं पकड़े गए आरोपी**- 1-मनोज ताम्रकार उम्र 58 साल, 2-सुकेश ताम्रकार उम्र 25 साल, 3-चंद्रसेन ताम्रकार उर्फ सोमू उम्र 26 साल निवासी तपकरा 4-योगेश साहू उम्र 23 साल निवासी सिंगीबहार थाना तपकरा प्रार्थी विकास लकड़ा निवासी बंधाटोली थाना तपकरा ने 23 जुलाई 2024 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि नवंबर 2023 में ग्राम तपकरा के रहने वाले मनोज ताम्रकार एवं उसके 02 पुत्र सुकेश ताम्रकार, चंद्रसेन ताम्रकार उर्फ सोमू तीनों उनके घर आए थे. नौकरी लगाने की बात कहकर कुछ शर्तों को मानने कहा गया.

हाईकोर्ट में मुख्य सचिव ने पेश किया जवाब, कोर्ट ने इलाज के पर्याप्त इंतजाम के दिए निर्देश

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ में मलेरिया और डायरिया का प्रकोप फैला हुआ है. इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है. मामले में मुख्य सचिव की ओर से आज हाईकोर्ट में जवाब पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि मलेरिया और डायरिया कंट्रोल के लिए शासन और प्रशासन जुटकर कार्य कर रहा है. सभी प्रभावित क्षेत्रों में मरीजों का इलाज किया जा रहा है. कैंप लगाए जा रहे और जांच के बाद दवा दी जा रही है. लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है. कोर्ट ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि मरीजों को उपचार से वंचित नहीं होना पड़ेगा. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने निर्देश दिए कि कोई भी मरीज बिस्तर या दवा के अभाव में अस्पताल से न लौटे. साथ ही कोर्ट ने उपचार के पर्याप्त इंतजाम करने और रोग फैलने से रोकने के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई अब 13 अगस्त को रखी है. दरअसल, बिलासपुर जिले के टेंगनमाड़ा में दो बच्चों की मलेरिया से मौत, कांवड़ में मरीज को अस्पताल ले जाने और प्रदेश में कई स्थानों पर मलेरिया से मौत की खबर पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है. चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने 18 जुलाई को राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा था.

मोदी सरकार में बढ़ा एसईसीआर बिलासपुर का बजट

केंद्रीय रेल मंत्री वैष्ण ने की 6922 करोड़ के आवंटन की घोषणा

रायपुर/ नई दिल्ली। संसद में 23 जुलाई को 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश किया गया. इसी संदर्भ में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रेसवार्ता कर रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं और नई योजनाओं के लिए बजट प्रावधान की जानकारी दी. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूपीए सरकार के समय बिलासपुर स्श्वष्टक्र को लगभग 311 करोड़ रुपये का बजट मिलता था. एनडीए मोदी सरकार में यह बजट 22 गुना बढ़कर 6922 करोड़ रुपये हो गया है. यह राशि 37,000 प्रोजेक्ट्स पर खर्च की जाएगी, जिससे बिलासपुर स्श्वष्टक्र रेलवे का समुचित विकास सुनिश्चित होगा.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेसवार्ता में बताया कि छत्तीसगढ़ में 2009-2014 के बीच औसतन 6 किलोमीटर प्रति वर्ष रेल लाइन का निर्माण हुआ था, जबकि 2014-2024 के बीच यह औसत 100 किलोमीटर प्रति वर्ष रहा. छत्तीसगढ़ में रेल लाइन का 100त्न विद्युतीकरण किया गया है, जिसमें 2014-2024 के दौरान 31 किलोमीटर प्रति वर्ष रेल लाइनों का विद्युतीकरण शामिल है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 37,018 करोड़ रुपये की लागत से 2,731 किलोमीटर की 25 नई रेल लाइन परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है. अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राज्य के 32 स्टेशनों का विकास किया जा रहा है, जिसमें अकलतरा, अंबिकापुर, बैकुंठपुर रोड, बालोद, बाराद्वार, बिल्हा, भानुप्रतापपुर, भाटापारा, भिलाई, भिलाई नगर, भिलाई पावर हाउस, बिलासपुर, चांपा, दल्लीराजहरा, डोंगरगढ़, दुर्ग, हथबंध, जगदलपुर, जांजगीर नैला, कोरबा, महासमुंद, मंदिर हसौद, मरौदा, निपनिया, पेंड्रा रोड, रायगढ़, रायपुर जंक्शन, राज नांदगांव, सरोना, तिल्दा-नेवरा, उरकुरा और उसलापुर स्टेशन शामिल हैं. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014 से अब तक छत्तीसगढ़ में 141 रेल ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज का निर्माण किया गया है.

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में लाइनों की क्षमता बढ़ाने के लिए दोहरीकरण, तिहरीकरण और चौथी लाइन के कार्य वृहद रूप से किए जा रहे हैं.

छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में 368 अटल टिंकरिंग लैब्स का सफल संचालन

रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत राज्य के 33 जिलों में कुल 368 अटल टिंकरिंग लैब्स संचालित करने की घोषणा की है। इनमें से 278 लैब्स शासकीय विद्यालयों में और 90 लैब्स अशासकीय विद्यालयों में संचालित हो रहें हैं। इन लैब्स का मुख्य उद्देश्य युवाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में सशक्त बनाना है। राज्य स्तर पर अटल टिंकरिंग लैब्स की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कई विद्यालयों में आवश्यकताओं की पूर्ति में कमी है। इसके समाधान हेतु राज्य सरकार ने 03 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें ञरु शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। इस दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि संचालित लैब्स का फीडबैक प्राप्त कर अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों को भी इनका उपयोग करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। ञरु संबंधित गतिविधियों को अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु विद्यालय प्रारंभ अथवा विद्यालय बंद होने के 02 घंटे पूर्व अथवा बाद की समयावधि में किया जायेगा। जिला एवं राज्य स्तर से ञरुलैब का नियमित निरीक्षण किया जायेगा। समय-समय पर जिला स्तर पर आयोजित गतिविधियों में ञरुलैब की गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाये एवं गतिविधियों में सम्मिलित विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को उनके कार्य के आधार पर पुरस्कृत किया जाये। जिले से पुरस्कृत विद्यार्थियों को राज्य स्तर पर होने वाले ञरु मैराथन में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। समस्त जिलों के कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने जिलों में संचालित ञरु के विद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक आयोजित कर फीडबैक प्राप्त करें। साथ ही, अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों को भी इन लैब्स का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.